राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 229 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,11 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

पपला गुर्जर के छुपाए हथियार बरामद

अलवर, (एजेंसी)। राजस्थान में अलवर जिले के बहरोड़ थाना पुलिस ने बुधवार को एनसीआर के कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर के हरियाणा में एक गांव में छुपाए विदेशी हथियार और अन्य असला बरामद किया है। जयपुर के आईजी हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि इसके साथ ही फरारी के दौरान उसका सहयोग करने वाले महिपाल गुर्जर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि पपला से पूछताछ के बाद हरियाणा में कसौली थाना क्षेत्र के एक गांव में दबिश देकर एक एके-47, दो विदेशी पिस्टल एवं 32 कारतूस बरामद किए गये हैं।

नदी में गिरी महिला को मरीन कमांडो ने बचाया

पणजी, (एजेंसी)। भारतीय नौ सेना के मरीन कमांडो ने गोवा की मनडोवी नदी में गिरी एक महिला को बचाने में सफलता हासिल की है। नौ सेना की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार मनडोवी नदी में मरीन कमांडो अपने नियमित गशत पर थे तभी चालक दल ने एक महिला के पंजिम पुल से गिरते हुए देखा। नौका चालकों ने तुरंत नौका उस ओर मोड ली और मरीन कमांडो ने डूब रही महिला को बचा लिया। पीड़ित महिला को नाव में लाकर प्राथमिक उपचार दिया गया और एक रेजीडेंट्स नौसैनिक डॉक्टर की चिकित्सीय जांच के बाद महिला की हालत बेहतर पायी गयी।

उरी में सीमा पर घुसपैठ नाकाम, आतंकी ढेर

श्रीनगर, (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सतर्क सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। सैनिकों ने मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात आतंकवादियों के एक समूह को पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से भारी गोलीबारी की आड़ में पाक के कब्जे वाले कश्मीर सीमा के इस तरफ उरी सेक्टर के कमलकोट में घुसपैठ की कोशिश करते देखा। जब घुसपैठियों को चुनौती दी गई तो उन्होंने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया।

अकबर मानहानि मामला में 17 तक टला फैसला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा यौन शोषण के लगाए गए आरोपों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की ओर से दायर मानहानि मामले में बुधवार को सुनाये जाने वाले फैसले को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया। राउज एवेन्यू अदालत के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार पांडेय ने फैसला सुनाने की तिथि को इसलिए टाल दिया क्योंकि कुछ लिखित प्रस्तुतियाँ बुधवार को देर से अदालत में पेश की गई। इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद एक फरवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

महापत्तन प्राधिकरण बिल पर संसद की मुहर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी- सरकारी भागीदारी के साथ संचालित करने तथा उन्हें और अधिक स्वायता देने से संबंधित महापत्त प्राधिकरण विधेयक 2020 को बुधवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई जिसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गई। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा ने बुधवार को इस विधेयक को मत विभाजन के दौरान 44 के मुकाबले 84 मतों से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे 23 सितंबर 2020 को पारित किया था। यह महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लेगा।

मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

नक्सलियों की रिहाई की मांग कर आंदोलन को अपवित्र बनाने का किया प्रयास

नई दिल्ली ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानून, किसान आंदोलन और बजट सहित अन्य मामलों पर सरकार का पक्ष सदन के पटल पर रखा था। जिसमें विपक्ष ने आठ बार हंगामा मचाया।

संबोधन की मुख्य बातें

- पीएम मोदी ने एक बार फिर से किसानों से अपील की कि टेबल पर बैठकर, मिलकर समस्या का समाधान करें।
- एक और महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है वो यही 10,000 एफपीओ बनाने का। यह छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं। महाराष्ट्र में एफपीओ बनाने का विशेष प्रयोग हुआ है। केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी में एफपीओ बनाने के काम में लगे हुए हैं।
- मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने फायदे के लिए उठाते हैं तो क्या होता है। नक्सलवादी, आतंकवादी आदि जो जेल में बंद हैं, उनकी फोटो लेकर रिहाई की मांग करना किसान आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है।
- पीएम मोदी ने कहा कि देश में पब्लिक सेक्टर जितना जरूरी है, उतना ही प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है।
- हमने किसानों के इंफ्रास्टक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
- हम धीरे-धीरे किसानों को फल, फूल और सब्जी उत्पादन की तरफ ले जा सकते हैं।
- बड़ा बदलाव करके हमारे किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा। हमारे किसान से छोटे किसानों को बीज से लेकर बाजार तक मुहैया कराई है।
- सत्ता में हो या विपक्ष में हर किसी को किसानों के लिए काम करने की आवश्यक्ता है। किसानों को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है।
- हमारे यहां एग्रीकल्चर समाज के कल्चर का हिस्सा रहा है। हमारे पर्व, त्योहार सब चीजें फसल बोने और काटने के साथ जुड़ी रही हैं। यहा राजा जनक और कृषि के भाई बलराम ने भी हल चलाई है।
- कृषि के क्षेत्र में बदलाव की आवश्यक्ता है। हमारे यहां संभावना है। किसानों को सही तरीके से गाइड करना होगा।

ना खेलब ना खेलन देब, खेलबे बिगाड़ब: प्रधानमंत्री

पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों पर विस्तार से जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी की एक कहावत के जरिए विपक्ष को खेल बिगाड़ने वाला बताया। पीएम ने कहा, खेलब ना खेलन देब, खेलबे बिगाड़ब। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार के पुराने बयानों को सहारा लेकर घेरा। पीएम मोदी ने शरद पवारों के उन बयानों का जिक्र किया जिसमें उन्होंने एपीएमसी ऐक्ट में बदलाव और प्राइवेट मंडियों का समर्थन किया था। पीएम मोदी ने कहा कि यह भी कहा कि विपक्षी दलों की सरकारें भी जिन राज्यों में हैं वहां कुछ ना कुछ रिफॉर्म किए हैं। हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 सौ कानून खत्म किए हैं। हम तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं।

कृषि कानून विकल्प के तौर पर हैं, सभी के लिए जरूरी नहीं

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हैरान हूं कि पहली बार सदन में यह तर्क आया कि जब मैंने मांगा नहीं तो दिया क्यों। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि यह विकल्प के तौर पर है। सभी के लिए जरूरी नहीं है। इस देश में दहेज के खिलाफ कानून बना, लेकिन उसकी किसी ने मांग नहीं की थी। तीन तलाक पर कानून की किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी कानूनों की जरूरत थी, इसलिए बनाया। शिक्षा के अधिकार की मांग किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन बदलाव के लिए जरूरी था तो सरकार ने बनाया। प्रधानमंत्री जिस समय कृषि कानूनों पर बोल रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने हंगामा किया।

टोकाटाकी पर भड़के पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब दिए। इस दौरान पीएम मोदी लय में नजर आए। खेती से जुड़े कानूनों का बचाव करते हुए जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी टोकने लगे। इस पर पीएम मोदी ने पहले हंसते हुए उन्हें चुप कराया। नोक-झोंक के बीच मोदी ने स्पीकर से कहा कि यह सब भी चलते रहना चाहिए, लेकिन जब टोकाटाकी बढ़ गई तो प्रधानमंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि न कहीं मंडी बंद हुई और न ही एमएसपी बंद हुई। वहीं, कानून बनने के बाद एमएसपी के तहत खरीद बढ़ी है। इस पर अधीर रंजन खड़े हो गए और हंगामा करने लगे।

मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार किसानों का सम्मान करती है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 के बाद की दुनिया, सदन में महिलाओं के महत्व पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति (रामनाथ कोविंद) के भाषण ने भारत की संकल्प शक्ति को प्रदर्शित किया। उनके शब्दों ने भारत के लोगों के बीच विश्वास की भावना को उत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण के दौरान बड़ी संख्या में महिला सांसद मौजूद रहीं। यह एक महान संकेत है।

दिल्ली लाल किला हिंसा का आरोपी इकबाल बंदी

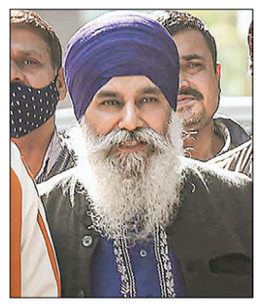

नई दिल्ली ■ एजेंसी

गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा मामले में आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने देर रात पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया है।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इकबाल सिंह को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इकबाल सिंह को सात दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब क्राइम ब्रांच इकबाल से पूछताछ कर हिंसा में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं और कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने इकबाल सिंह को सात दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान जज ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इकबाल सिंह की तरफ से वकील कौन हैं। जवाब में पुलिस ने कहा आरोपी का कोई वकील नहीं हैं। जिसपर जज ने इकबाल के लिए सरकारी वकील मुहैया करवाने के लिए कहा।

7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया

दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मृतक किसान नवरीत सिंह का परिवार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के आईटीओ पर कथित तौर पर ट्रैक्टर पलटने से मरे 25 वर्षीय किसान नवरीत सिंह के परिवार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में घटना की एसआईटी जांच कराने का अनुरोध किया है।

मृतक नवरीत सिंह के दादा हरदीप सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। हरदीप सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि अपने पोते की मौत की सही और निष्पक्ष जांच एवं न्याय पाने के साथ सच्चाई जानने का उन्हें अधिकार है। पुलिस के मुताबिक, नवरीत सिंह की मौत आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई थी जो पूर्व निर्धारित ट्रैक्टर परेड के रास्ते से इतर गाजीपुर बॉर्डर से प्रदर्शन के लिए कई किसानों के साथ वहां पहुंचा था।

18 को किसानों का रेल रोको अभियान

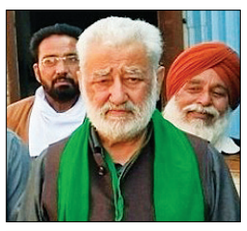

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 18 फरवरी को देश भर में कुछ देर के लिए ट्रेनों के पहिये थम जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले दो महीने से अधिक समय से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जमे हजारों किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। किसान नेताओं ने बिल के खिलाफ 18 फरवरी को पूरे देश भर में 4 घंटे के लिए रोल रोको अभियान की घोषणा कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में बताया कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलेगा। इसके अलावा किसान नेताओं ने घोषणा की है कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा किसान फ्री कराएंगे। टोल संग्रह नहीं करने दिया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर इस महीने के शुरू में उन्होंने तीन घंटे के लिए चक्का जाम किया था।

देश में चार घंटे के लिए थम जाएंगे ट्रेनों के पहिये

14 फरवरी को पुलवामा हमले की सालगिरह पर कैंडल मार्च करेंगे

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 14 फरवरी पुलवामा की सालगिरह पर जवान और किसान के लिए कैंडल मार्च और मशाल रैली निकाली जाएगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर किसान सॉलिडैरिटी शो करेंगे।

किसानों को एनआईए ने समन नहीं भेजा

वहीं बुधवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को बताया कि एनआईए ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसान नेताओं को समन नहीं भेजा है।

ट्विटर को सस्पेंड करने ही होंगे 257 अकाउंट्स

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट पर रोक तो लगाई है लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब कर कई सवाल पूछे हैं।

सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। हालांकि बुधवार को ट्विटर ने बताया 500 से अधिक सस्पेंड कर दिए गए हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। वहीं, सरकार की ओर से ट्विटर को कहा गया है अभिव्यक्ति की आजादी और आलोचना का अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार के खिलाफ नरसंहार करने के शब्दों और हेशटैग के दुरुपयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले भारत सरकार ने ट्विटर से कुछ अकाउंट्स हटाने को कहा था, जिनका संबंध किसान आंदोलन से था, साथ ही खालिस्तानी समर्थक हैशटेग भी चलाने का आरोप था। इन अकाउंट्स को ट्विटर ने हटा दिया था।

ट्विटर के अड़ियल रवैये पर केंद्र भी सख्त

भारत और चीन सीमा पर नौ महीने बाद दिखी शांति

दोनों देशों ने पैंगोंग त्सो से हटाने शुरू किए टैंक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत और चीन के बीच पिछले साल से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच दोनों पक्षों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे से टैंकों और इन्फैंट्री युद्धक वाहनों को वापस लाना शुरू कर दिया है।

यह जानकारी बुधवार को इस डिसइंगेजमेंट योजना के संबंधित अधिकारियों ने दी। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात का एलान करने के बाद कि बीजिंग ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन अहम रणनीतिक चोटियों पर सैनिक अभी भी मौजूद हैं। पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के कई बिंदुओं में से एक से बख्तरबंद वाहनों और उपकरणों की वापसी की खबर दोनों देशों के बीच हुई पिछली कमांडर स्तरीय वार्ता के करीब 15 दिन बाद आई है। दोनों पक्षों ने सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर 24 जनवरी को बैठक कर चर्चा की थी।

दोनों पक्षों के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू किया

चीनी रक्षा मंत्रालय और चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वु कियान ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। उनके इस बयान से संबंधित खबर चीन के आधिकारिक मीडिया ने साझा की है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की नौवें दौर की वार्ता (24 जनवरी को) में बनी सहमति के अनुरूप दोनों देशों के सशस्त्र बलों की अग्रिम पंक्ति की इकाइयों ने 10 फरवरी से यह कदम उठाया है।

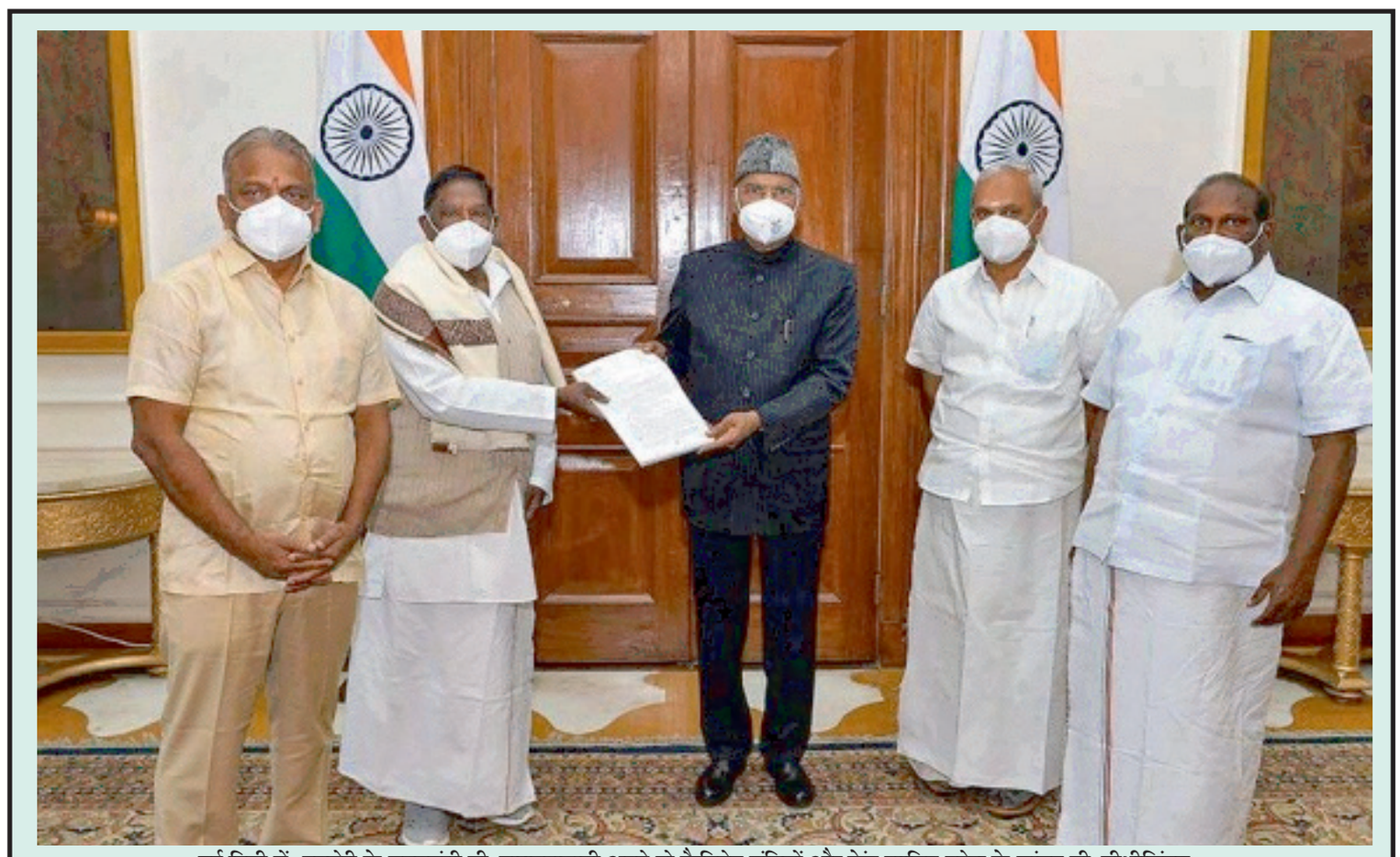

नई दिल्ली में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी अपने दो कैबिनेट मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के सांसद वी. वीथीलिंगम के साथ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपते हुए।

गोवा के 10 विधायकों की अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष 26 फरवरी को करेंगे सुनवाई

नई दिल्ली । गोवा में 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली अर्जी पर स्पीकर 26 फरवरी को विचार करेंगे। ये विधायक जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी।

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मामले को मार्च के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। कोर्ट कांग्रेस नेता गिरीश चोडनकर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते..हम आदेश में मामले के निपटारे के लिए कह रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि इन 10 विधायकों में से नौ कांग्रेस उम्मीदवार थे और वे 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे, जबकि एक अन्य 2019 के उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे।

अगस्त, 2019 में अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल किए जाने के बाद डेढ़ साल बीत गए, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों और केंद्रीय विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाई के साधन लैपटॉप व इंटरनेट आदि उपलब्ध कराने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के गत वर्ष 18 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकरण में जुटा है उत्तर कोरिया : यूएन

संयुक्त राष्ट्र। यूएन एक्सपर्ट ने बताया कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों व बैलिस्टिक मिसाइलों के आधुनिकीकरण में जुटा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस पर रोक लगाई गई है लेकिन उत्तर कोरिया ने इसे दरकिनार करते हुए इन प्रोग्राम में इस्तेमाल के लिए दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी व

मटीरियल मंगवाने का सिलसिला जारी रखा है। यह जानकारी एक्सपर्ट के एक पैनल ने दी जो उत्तरपूर्व एशियाई देशों पर लागू प्रतिबंधों की निगरानी करता है। पैनल ने यह रिपोर्ट सुरक्षा परिषद के सदस्यों को सोमवार को भेजा है। इसमें कहा है कि किम जोंग उन की सरकार परमाणु हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का उत्पादन कर रहा है और अपने परमाणु शस्त्रागारों की रखरखाव कर रहा है।

पिछले माह ही उत्तर कोरिया में आयोजित एक परेड में पनडुब्बियों और अन्य सैन्य उपकरणों से वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की झलक देखने को मिली जो वहां के नेता किम जोंग-उन के परमाणु हथियार कार्यक्रम का विस्तार करने के आह्वान के अनुरूप है। पैनल ने बताया, 'सैन्य परेड में यहां नए कम दूरी, मध्यम दूरी, सबमरीन व बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का डिस्प्ले किया गया था।' बीते दिनों 'वर्कर्स पार्टी कांग्रेस' की आठ दिवसीय बैठक के दौरान किम ने अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने और अधिक उन्नत परमाणु हथियार प्रणालियों को विकसित करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अमेरिका के साथ संबंध इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियां त्यागता है या नहीं।

कोविड-19 ने छीन ली अमेरिकी सांसद रॉन राइट की जिंदगी, राष्ट्रपति बाइडन ने बताया 'बहादुर'

वाशिंगटन। अमेरिका में कोविड-19 की चपेट में आने के बाद यूएस कांग्रेस के सांसद रॉन राइट का निधन हो गया है। वे ऐसे पहले सांसद हैं जिनका इस महामारी की वजह से निधन हुआ है। रॉन टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद थे। उन्हें और उनकी पत्नी सुसान को पिछले माह ही कोविड-19 टेस्ट में पॉजीटिव पाया गया था। इसके बाद से ही दोनो का डलास के अस्पताल में इलाज चल रहा था। रॉयटर्स के मुताबिक 67 वर्षीय रॉन काफी समय से केंसर की समस्या से भी जूझ रहे थे। वो पहली बार वर्ष 2018 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे। इसके बाद उन्हें विदेश मामलों, शिक्षा और लेबर कमेटी में भी जगह दी गई थी। उनका पूरा नाम रोनाल्ड जैक राइट था।

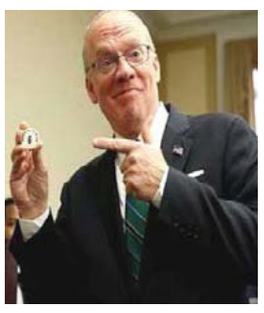

21 जनवरी को जब उनका टेस्ट पॉजीटिव आया था उस वक्त उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्हें इसके हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं लेकिन वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोगों के लिए अपना काम करते रहेंगे। उनके निधन पर सदन की स्पीकर नैंसी पोलेसी ने भी दुख व्यक्त किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि रॉन हमेशा ही टेक्सास के लोगों के हितों को लेकर गंभीर रहे और काम करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 से होने वाली हर मौत उन्हें एक धक्का दे जाती है और बेहद दुख पहुंचाती है।

इनके साथ ही सांसद केविन मैकर्थी ने उन्हें एक बहादुर इंसान बताते हुए कहा है कि ये वक्त उनके लिए काफी दुख वाला है। इनके अलावा राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी रॉन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो एक बहादुर सांसद थे जो अंत तक भी इस महामारी और केंसर से बहादुरी से लड़े। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश इस महामारी से तब तक लड़ता रहेगा जब तक इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता। बाइडन ने रॉन के परिवार को सांत्वना दी है। आपको बता दें कि यूएस कांग्रेस के करीब दर्जन भर सांसदों को पिछले एक वर्ष में कोविड-19 पॉजीटिव पाया जा चुका है।

इससे पहले लुसियाना के रिपब्लिकन सांसद ल्यूक लेटलॉ का भी निधन इस महामारी की चपेट में आने के बाद हो गया था। हालांकि उस वक्त तक उन्हें सीनेट की सदस्यता की शपथ नहीं दिलाई गई थी। रॉयटर्स के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 महामारी की चपेट में आने के बाद अब तक करीब 463,911 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में इसके अब तक करीब 27,073,858 मामले सामने आ चुके हैं और 12,324,032 इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका बीते कई माह से कोविड-19 संक्रमण और इससे होने वाली मौतों के मामलों में लगातार दुनिया में पहले नंबर पर बना हुआ है। बाइडन ने सत्ता में आने के बाद इससे तेजी से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

म्यांमार में फौज को जनता की चुनौती

सैन्य शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बोले- हमें कर्फ्यू की परवाह नहीं, देश में लोकतंत्र वापस चाहिए

नेपितॉ। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद जनता पूरी ताकत से सड़कों पर उतर आई है। सेना ने देश के ज्यादातर शहरों और कस्बों में कर्फ्यू लगाया है, लेकिन लोगों के जोश के आगे वह मजबूर होकर चुपचाप तमाशा देख रही है। मंगलवार को सुबह से ही लोग यांगून और बाकी शहरों में सड़कों पर उतर आए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा- हम अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र खत्म होते नहीं देख सकते। कर्फ्यू की कोई परवाह नहीं, लोकतंत्र वापस चाहिए।

अस्पतालों और दफ्तरों में नहीं पहुंचे वर्कर्स

1 फरवरी को तख्तापलट के बाद सेना ने 5 फरवरी को देश के किसी भी हिस्से में लोगों के जुटने या रैली करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद विरोध और तेज होता जा रहा है। 'द गार्डियन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को सुबह से ही लोग सड़कों पर उतर आए और सैन्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान सैनिक चुपचाप खड़े देखते रहे। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं पहुंचे।

यांगून के ऐतिहासिक सुले पगोडा के करीब सुबह ही हजारों लोग पहुंच गए। इस बीच खबरें फैलीं कि सेना इन लोगों के खिलाफ बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन, लोगों की संख्या और उनके हौसले को देखकर सैनिक चुपचाप खड़े रहे। 37 साल की विन मिन ने कहा- हम जानते हैं कि सेना हमारी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।

तानाशाही नहीं चलेगी

मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथ में बैनर्स ले रखे थे। इन पर लिखा था- हमारी नेता आंग सान सू की को फौरन रिहा किया जाए। अब देश में तानाशाही सहन नहीं की जाएगी। लोकतंत्र लोगों का हक है और लोगों ने ही सेना को सम्मान दिलाया है।

स्कूल टीचर थेइन विन ने कहा- अगर सेना यह सोचती है कि इस जुल्म से लोग डर कर घर में छिप जाएंगे तो यह उसकी गलतफहमी है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब लोग सड़क पर उतर आए हैं और सेना को लोकतांत्रिक सरकार की बहाली करनी होगी। यहां सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। इंटरनेट पर प्रतिबंध की आलोचना की।

मोदी और बाइडेन ने भी म्यांमार पर चर्चा की

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार रात 11 बजे फोन पर बातचीत की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस दौरान म्यांमार में तख्तापलट और उसके बाद के हालात पर भी बातचीत हुई। तख्तापलट के बाद बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका वहां प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि, अब तक उसने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है।

चीन को कोरोना कम्यूनिटी ट्रांसमिशन का डर

नए साल के बीच ड्रैगन ने सख्त गाइडलाइन जारी की, पाबंदियों का लोगों ने किया विरोध

बीजिंग। दुनियाभर में कोरोना महामारी फैलाने वाला चीन अब खुद इस संक्रमण से डरने लगा है। दरअसल, चीन में 12 फरवरी से 'लूनर न्यू इयर' शुरू हो रहा है। इस दौरान चीन में सरकारी छुट्टी रहती है। करोड़ों लोग नया साल मनाने के लिए ट्रैवल करेंगे। ऐसे में सरकार को कोरोना संक्रमण के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन का डर सताने लगा है। अब चीनी प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कड़ी गाइडलाइन जारी की है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। चीन में नए साल के दौरान करोड़ों लोग अपने गांव या बाहर घूमने निकलते हैं। इस दौरान बस, ट्रेन और एयरपोर्ट पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती। सड़कों पर भी वाहनों की लाइन लगी रहती है। चीन के उत्तर-पूर्वी प्रांत में एक ही दिन में 2000 कोरोना के नए केस ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है।

चीनी हेल्थ कमिशन की गाइडलाइन में ये सब

जो लोग गांव से लौटेंगे, उन्हें 7 दिन पहले का Covid-19 निगेटिव

टेस्ट दिखाना होगा। साथ ही 14 दिन होम क्वारैंटाइन में रहना होगा।

जो लोग बाहर से आएंगे, उन्हें 14 दिन सरकार द्वारा तय किए गए क्वारैंटाइन होटल में बिताना होगा। वे अपने घर नहीं जा सकेंगे।

स्वॉब के अलावा मल के सैंपल टेस्ट को लेकर चिंता

नए साल के सेलिब्रेशन के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही उन्हें कोरोना बचाव के लिए जारी सरकारी गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करना होगा। लोगों की सबसे बड़ी चिंता मल के सैंपल जांच को लेकर है। गले और नाक के स्वॉब टेस्ट के अलावा चीन में मल टेस्ट भी किया जा रहा है। ऐसे में लोग इससे बचने के लिए न्यू इयर प्लान कैंसिल कर रहे हैं।

इस बार रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट खाली-खाली

सरकार की सख्त गाइडलाइन के बाद लोगों ने अपने ट्रैवलिंग प्लान कैंसल कर दिए हैं। पिछले साल नए साल में भीड़ से भरे बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर इस बार लोग नहीं दिख रहे हैं। सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है।

लोगों ने पूछा- आपका दिमाग किस चीज से बना है

सरकारी गाइडलाइन का चीन की सोशल मीडिया पर विरोध भी शुरू हो गया है। एक व्यक्ति ने Weibo पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'क्या विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल फैसिलिटी हर किसी को हर 7 दिनों में कोरोना वायरस टेस्ट की अनुमति देती है? क्या टेस्ट के लिए एकत्र होने से संक्रमण का बड़ा खतरा नहीं है? इसके अलावा, राज्य केवल हमें 7 दिन की छुट्टी देते हैं और अब आप 14 दिनों के लिए होम क्वारैंटाइन करेंगे। आपका दिमाग किस चीज से बना है?'

भगौड़ा घोषित विजय माल्या को कानूनी खर्चे व रहन-सहन के लिए लंदन हाईकोर्ट अपने खजाने से देगा पैसा

लंदन। भारत में भगौड़ा घोषित शराब कारोबारी विजय माल्या को अपने कानूनी रहन-सहन के खर्चे पूरे करने के लिए लंदन हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है। माल्या को अपने रहन-सहन व खर्चे के लिए कोर्ट ने अपने पास जमा कोष से 11 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। अदालत के मुताबिक माल्या को कोर्ट से कुछ पैसे निकालने की इजाजत दी गई है। इस धन का उपयोग वह अपने जीवन यापन के खर्चे और कानून प्रक्रिया के भुगतान में कर सकता है। दिवालिया एवं कंपनी मामलों की उप अदालत के जज निगेल बर्नेट ने इस मामले की सुनवाई की।

अदालत के फैसले के मुताबिक माल्या को कोर्ट के कोष से कुछ पैसे निकालने की अनुमति दी गई है। इस धन का वह अपने जीवन यापन के खर्चे और कानूनी प्रक्रिया के भुगतान कर सकेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विजय माल्या अब तक दो पहलुओं पर सफल रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता भारतीय बैंक माल्या के आवेदन के खिलाफ पक्ष रखने में काफी हद तक सफल रहे हैं। माल्या को अपने रहन-सहन व खर्चे के लिए कोर्ट ने अपने पास जमा कोष से 11 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। रकम में से माल्या को रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए करीब 11 लाख पाउंड निकालने की अनुमति दी है। बता दें कि किंगफशिर एयरलाइंस का पूर्व प्रमुख माल्या जमानत पर ब्रिटेन में हैं। माल्या धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किए जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुका है। गौरतलब है कि माल्या पर 17 भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। माल्य 2 मार्च, 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन की अदालत से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की थी।

चीन में गिरफ्तार हुई ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार, सीक्रेट जानकारी लीक करने का संदेह

बीजिंग। ऑस्ट्रेलिया की महिला पत्रकार को चीन ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 6 माह तक उन्हें नजरबंद रखा गया था। उनपर देश की गुप्त सूचनाओं को विदेशों में लीक करने का आरोप है। वो यहां पर स्थानीय टीवी चैनल में काम करती थी। गिरफ्तार की गई 49 वर्षीय पत्रकार चेंग ली ने अधिकारियों से आग्रह किया कि उन्हें उनके दो छोटे बच्चों से मिलने की अनुमति दी जाए।

चेंग ली चाइना सेंट्रल टेलीविजन के अंग्रेजी न्यूज चैनल सीजीटीएन में एंकर थीं। पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी तब दी गई जब परिवार ने उनके दो बच्चों को चेंग से मिलने देने का अनुरोध किया। चीन में जन्मी पत्रकार अपने माता-पिता के साथ बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थीं। उनकी पढ़ाई वहां के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में हुई। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के कारण स्कूल की छुट्टियों के दौरान उनके बच्चे स्कूल की छुट्टियों में अपने ग्रैंडपैरेंट्स के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। दोनों बच्चों की उम्र 9 और 11 साल है। 5 फरवरी को गिरफ्तार पत्रकार चेंग की ओर से परिवार के प्रतिनिधि ने कहा, हम चीन की

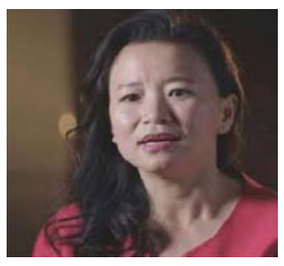

न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पेन और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को मामले की जानकारी दी। पिछले साल से दोनों देशों के बीच काफी तनाव है। दरअसल कैनबरा की ओर से कोरोना वायरस को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जांच की मांग की गई।

हिंदू अल्पसंख्यक और उनके धर्मस्थलों की हालत

पाकिस्तान में मंदिरों की दुर्दशा उजागर, भू-माफियाओं के निशाने पर 287 धर्मस्थल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की दुर्दशा को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि देश में हिंदू धर्म के प्रमुख स्थलों की हालत निराशाजनक है। रिपोर्ट में खेद जताया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाला एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश प्राचीन और पवित्र स्थलों की देखभाल में विफल रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह रिपोर्ट 5 फरवरी को एक सदस्यीय डॉ. शोएब सूडल आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी, जिसे पाक सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईटीपीबी के मुताबिक, 365 मंदिरों में से सिर्फ 13 मंदिरों का ही प्रबंधन उनके पास है। जबकि 65 मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी हिंदू समुदाय पर छोड़ी गई है।

इसका मतलब है कि 287 मंदिर भूमि माफियाओं के अधिग्रहण के लिए छोड़ दिए गए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 6 और 7 जनवरी को आयोग ने क्रमश- चकवाल में कटास राज मंदिर, मुल्तान में चकवाल और प्रह्लाद मंदिर का दौरा किया था।

रिपोर्ट में पाकिस्तान के 4 सबसे अधिक

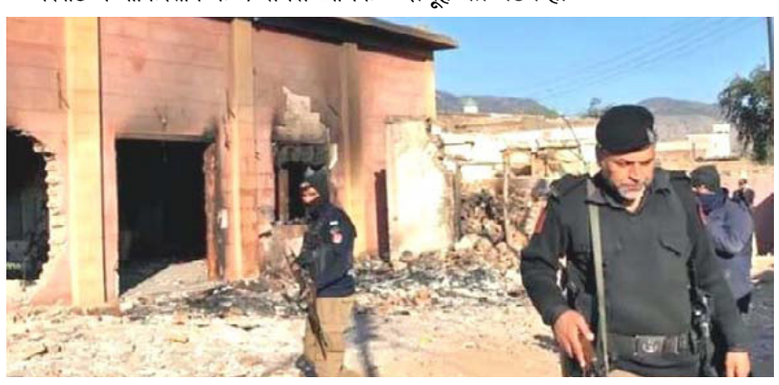

मान्यता वाले स्थलों में से 2 की बदहाल स्थिति की तस्वीरें भी दिखाई गई है। आयोग ने दो अहम सुझाव भी दिए हैं। पहला- अल्पसंख्यक समुदायों के पवित्र धार्मिक स्थलों के पुनर्वास के लिए एक कार्यकारी समूह बनाया जाए। दूसरा- खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में निर्जन टेरी मंदिर/समाधि का जीर्णोद्धार करने के ईटीपीबी को निर्देश दिए जाएं।

धार्मिक स्थलों के पुनर्वास के लिए समूह का गठन हो

आयोग ने रिपोर्ट में कोर्ट से मांग की है कि दोनों अल्पसंख्यक समुदायों के पवित्र धार्मिक स्थलों के पुनर्वास के लिए एक कार्यकारी समूह की स्थापना की जाए। साथ ही हैरानी जताते हुए कहा गया है कि तकनीक के इस युग में भी ईटीपीबी अभी तक अपनी संपत्तियों की जियो टैगिंग नहीं करा सकी है।

कोरोना दुनिया में: रूस पर महामारी से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने का शक, WHO ने कहा- एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को अभी खारिज न करें

वॉशिंगटन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.69 करोड़ से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 88 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 23 लाख 35 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं। महामारी से हुई मौतों को लेकर चीन के बाद अब रूस भी शक के घेरे में आ गया है। दरअसल, एक एजेंसी ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं, उनमें रूसी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या ज्यादा है।

सरकारी आंकड़ों पर सवालिया निशान

रूस में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा उससे ज्यादा हो सकता है जो सरकार ने जारी किया है। कम से कम रोस्टेट एजेंसी द्वारा जारी फिगर्स से तो यही अंदाजा लगता है। इसके मुताबिक, रूस में पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच कुल 1 लाख 62 हजार 429 लोगों की मौत हुई। हालांकि, रूस सरकार ने सोमवार को

जो आंकड़े दिए, उनके मुताबिक देश में अब तक कुल 77 हजार 68 लोगों की मौत संक्रमण से हुई। वहीं, जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक, रूस में अब तक कुल 75 हजार 828 लोगों की मौत वायरस से हुई है।

एस्ट्राजेनिका को खारिज न करें

WHO ने कहा है कि महामारी के खिलाफ जंग में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन अहम रोल निभा सकती है। संगठन का यह बयान ऐसे वक्त आया है जबकि साउथ अफ्रीका ने इसे नए वैरिएंट के खिलाफ कमजोर करार देते हुए इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। WHO ने कहा- यह पूरी तरह जल्दबाजी वाला फैसला है। इतने शुरुआती दौर में वैक्सीन को खारिज नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर यह कारगर साबित नहीं हुई।

यह मामला इसलिए बढ़ा

ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मालूम चला है कि ये वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर ज्यादा असरदार नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में वैक्सीन को 'निराशाजनक' बताया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री ज्वेली माखिसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एस्ट्राजेनेका की तरफ से साउथ अफ्रीका को 10 लाख डोज मिल चुके हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों की स्टडी के बाद आगे की सप्लाई को होल्ड कर दिया गया है। ज्वेली ने बताया कि साउथ अफ्रीका में 90त्न केस कोरोना के नए स्ट्रेन के ही हैं। ऐसे में अगर वैक्सीन ही असरदार नहीं होगी तो उसे लेने का फायदा नहीं है।

फ्रांस में फिर हालात बिगड़ने लगे

फ्रांस सरकार ने करीब दो महीने के लॉकडाउन के बाद तमाम प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाने शुरू कर दिए थे। हालात बहुत हद तक काबू में भी आने लगे थे, लेकन अब दिक्कतें फिर बढ़ने लगी हैं। यहां लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। सोमवार को यहां कुल मिलाकर 458 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। इसके एक दिन पहले यानी सोमवार को भी करीब इतने ही लोगों की मौत हुई थी।

नई दिल्ली में बुधवार को कोविद 19 वैक्सीन कल दूसरी पारी के टीकाकरण अभियान के लिए डिस्पेंसरी में पहुंचा।

हमारे पास एक शिशु-केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए : राजेंद्र पाल

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) और महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी), दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से बाल कल्याण समितियों (सीडब्लूसी), किशोर किशोर बोर्ड (जेजेबी) और जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत गठित सीडब्ल्यूसी, जिला स्तर पर मजिस्ट्रेटों की पीठ है, जो यौन हिंसा, बाल विवाह, तस्करी, अपराधों, मादक द्रव्यों के सेवन, भीख मांगने, बंधुआ मजदूरी के शिकार बच्चों के बचाव, पुनर्वास और एकीकरण के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य और इसलिए सीडब्लूसी इन बच्चों की रक्षा की पहली पंक्ति है। किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत गठित, न्यायिक संस्थाएं हैं जो उन मामलों की जांच करती हैं जहां बच्चे कानून के विरोध में आए हैं और तदनुसार उनके पुनर्वास के लिए सुधारकारी उपाय करते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को कानून का अनुश्रवण करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके और इसीलिए प्रशिक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सहयोग किया गया है, जो सीडब्लूसी/ खखइ / की भूमिकाएँ के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण की शुरूआत में डॉ रश्मि सिंह, निदेशक (डब्ल्यूसीडी) ने हितधारकों के बीच अभिसरण के महत्व और विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ संबंधों पर जोर दिया। सुश्री मधु के गर्ग, सचिव (डब्ल्यूसीडी) ने दिल्ली को बाल अनुकूल स्थान बनाने, और अन्य राज्यों और शहरों के लिए एक उदाहरण बनाने के अपने उद्देश्य को रखा। अनुराग कुंडू, अध्यक्ष, डीसीपीसीआर ने अधिकारों की अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच बड़े अंतराल की ओर संकेत किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे संस्थानों को अपनी प्रक्रियाओं को वास्तव में बाल केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें मार्च में एक और 3 दिनों का रिफ्रेशर कोर्स होगा, क महत्व का विवरण व्यक्त किया। प्रशिक्षण महत्वपूर्ण सर्वोच्च / उच्च न्यायालय के निर्णयों, और रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, संक्षिप्त और विस्तृत आदेशों का मसौदा तैयार करने और व्यक्तिगत चाइल्ड केयर प्लान की तैयारी जैसे व्यावहारिक कौशल पर चर्चा के साथ-साथ कानून की बारीक स्थिति बनाने पर केंद्रित है। डब्ल्यूसीडी मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम, आयोजन के मुख्य अतिथि, ने अपने उद्घाटन भाषण में उन परिस्थितियों के विश्लेषण के महत्व पर जोर दिया जो एक बच्चे को अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक हितधारक को उस कार्य के उद्देश्य को समझना चाहिए जो कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को न्याय मिले। उन्होंने सीडब्ल्यूसी और जेजेबी को सरकार के बिना शर्त समर्थन की पेशकश की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बच्चा अपने अधिकारों से वंचित न रहे। जस्टिस श्रीमान मदन बी. लोकुर (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मुख्य भाषण में अपने लंबे और प्रतिष्ठित न्यायिक कैरियर के आधार पर जोर दिया कि प्रत्येक हितधारक को बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर बच्चे को सर्वोत्तम सहायता दी जा सके। किशोर न्याय अधिनियम का सार बच्चों के पुनर्वास में निहित है, उन्होंने कहा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों में कई नियुक्तियां हाल ही में की गई हैं और इसलिए अधिकांश अधिकारी नए हैं। वास्तव में, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. के. गुबा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उहउ२ / खखइ के लिए लोगों के एक बहुत विविध पैनल का चयन किया है, जिसमें लिंग, जाति और पृष्ठभूमि के काम के आधार पर विभिन्न समूहों पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न समूहों का उचित प्रतिनिधित्व शामिल है। । रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर लीगल और एनजीओ बैकग्राउंड तक के पैनल, बच्चों के लाभ के लिए व्यापक स्तर के अनुभवों की अनुमति देते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब इंतजार के दिन होंगे और भी कम

नई दिल्ली, (संवाददाता)। यदि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए स्थानीय अथॉरिटी में 45 दिनों से अधिक की वेटिंग मिल रही है तो आवेदक दूसरे जिले की अथॉरिटी से लाइसेंस बनवा सकेंगे। लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार इस तरह की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस माह के दौरान ही यह व्यवस्था लागू हो सकती है। कोरोना के चलते बंद रहीं जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चलते परिवहन विभाग की पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। लगातार आ रहीं शिकायतों को देखते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इस मुद्दे पर चार से अधिक बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि लाइसेंस बनवाने या लाइसेंस संबंधी किसी भी कार्य के लिए 45 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

मनजीन्दर सिंह सिरसा ने दावा किया कि तीनों किसानों की जमानत गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के द्वारा करवाई : अनिल कुमार

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि तीन निर्दोष किसानों की जमानत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधिक एवं मानवाधिकार विभाग के अधिवक्तागण ने करवाइ है जबकि इसका झूठा श्रेय लेने की मंशा से अकाली दल के नेता मनजीन्दर सिंह सिरसा ने एक विडियो जारी कर दावा किया कि इन तीनों किसानों की जमानत गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के द्वारा करवाई गई है। श्री सिरसा का इस प्रकार का कृत्य निन्दनीय है। उन्हांने बताया कि जब भाजपा सरकार ने इन तीनों काले कानूनों को पास किया तब अकाली दल पूर्ण रूप से उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा था और अब बगैर किसान हित का कोई कार्य किए झूठी सहानुभूति लेने के लिए वें नित नए स्वांग कर रहे है।

चौ. अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधिक एवं मानवाधिकार विभाग के चैयरमेन एडवोकेट सुनिल कुमार के नेतृत्व में विभाग के 15 अधिवक्ताओं की टीम 18 दिसम्बर 2020 से शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रहे किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर रही है। 26 जनवरी 2021 की शर्मनाक घटना के बाद पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाइ करने के साथ-साथ अनेक निर्दोष किसानों को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। उन निर्दोष किसानों की पैरवी हमारे विभाग के अधिवक्तागण बिना किसी प्रचार व प्रसार के कर रहे है। इसी प्रक्रिया में विभाग की द्वारका जिला न्यायालय टीम ने बाबा हरिदास नगर थाने में दर्ज केस में लवप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह व जसविन्दर सिंह निवासी जिला मानसा पंजाब, की जमानत दिनांक 8 फरवरी 2021 को करवाई, लेकिन बड़ा ही दुख की बात है कि अकाली दल के नेता इसका झूठा श्रेय लेना चाह रहे है।

इस अवसर पर विधिक एवं मानवाधिकार विभाग के चैयरमेन एडवोकेट सुनिल कुमार ने विस्तार से बताया कि विभाग के अधिवक्तागण दिल्ली की हर एक जिला अदालत में किसानों को निशुल्क कानूनी सहायता गत दिसम्बर माह से ही प्रदान कर रहे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विभाग सिर्फ निर्दोष किसानों को ही निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है और उनका उन व्यक्तियों से कोई वास्ता नहीं है जिन्होंने अपने आकाओं के निर्देश पर एक षणयन्त्र के तहत 26 जनवरी को हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में विभाग के अधिवक्ताओं ने 4 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज करते हुए मांग की थी कि दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसानों को पानी, चिकित्सा व शोचालय इत्यादि सुविधाऐं प्रदान की जाए। उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुऐ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य को नोटिस जारी कर दिया है। तीनों किसानों की जमानत करवाने वाले अधिवक्ता विकास यादव, महासचिव विधिक एवं मानवाधिकार विभाग, दिल्ली प्रदेश ने बताया कि इन किसानों की जमानत करवाने में सिरसा का किसी भी प्रकार का काई योगदान नहीं है।

नई दिल्ली में बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अनिल कुमार ने डीपीसीसी कार्यालय में दिल्ली कांग्रेस के सोशल मीडिया अभियान का शुभारंभ किया।

18 फरवरी से शुरू होगी नर्सरी दाखिला प्रक्रिया

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली के निजी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दाखिला के लिए प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इसके तहत नर्सरी, केजी व पहली कक्षाओं में आवेदन किए जा सकेंगे। दाखिला के मानदंड अपनी वेबसाइट पर 17 फरवरी से अपलोड किए जाएंगे। नर्सरी एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 मार्च है। 9 मार्च को छात्रों के आवेदन का आंकड़ा स्कूल जारी करेंगे। इसके बाद 15 मार्च को मार्क्स अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद 23 मार्च को पहली लिस्ट जारी की जाएगी। 25 मार्च को दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके बाद 31 मार्च को दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 25 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। दिल्ली में आमतौर पर करीब 1700 स्कूलों के लिए नर्सरी के लिए दाखिलें नवम्बर माह के आखिरी सप्ताह में शुरू होते रहे हैं। इससे पहले डीओई दिशानिर्देश जारी कर स्कूलों को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहता है, जिसके बाद दिसम्बर में आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाती है। पिछले साल ऐसा नहीं किया गया था। दिल्ली सरकार ने दिसम्बर में कहा था कि कोविड-19 के मद्देनजर स्कूलों के नौ महीने से बंद होने के कारण नर्सरी के दाखिले की प्रक्रिया को रद्द करने प्रस्ताव पर गौर किया जा रहा है। स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले महीने नर्सरी की दाखिला प्रक्रिया रद्द करने से इनकार कर दिया था। नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, केजी के लिए 4 से 5 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल उम्र (31 मार्च 2020) की आयु सीमा तय की है। राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिला शिक्षा निदेशालय के निदेर्शों पर होता है। निदेशालय प्रत्येक वर्ष दाखिला प्रक्रिया कार्यक्रम जारी करने के साथ ही स्कूलों व अभिभावकों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करता है।

घर में महिला की गला रेतकर हत्या

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली के किशनगढ़ थाना इलाके में सोमवार रात एक महिला की घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय पति तुगलकाबाद गया हुआ था, जबकि महिला का दोस्त घर में था। वही महिला को लेकर फोर्टिस अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पहुंची किशनगढ़ थाना पुलिस महिला के पति शाकिब व दोस्त सुमित से पूछताछ कर रही है।

दक्षिण-पश्चिमी जिला डीसीपी इंगित प्रताप सिंह का कहना है कि मूल रूप से यूपी में बुलंदशहर की रहने वाली तरन्नुम उर्फ हिना (32) पति शाकिब के साथ किशनगढ़ गांव में किराए पर रहती थी। तरन्नुम का दोस्त सुमित भी इनके साथ रहता था। तरन्नुम व शाकिब के दो बच्चे हैं, जो बुलंदशहर में दादा-दादी के पास रहते हैं।

दिल्ली मेट्रो : जल्द ही सभी सीटों पर सफर कर सकेंगे यात्री

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली मेट्रो यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। साढ़े पांच महीने बंद रहने के बाद संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी एहतियात के साथ मेट्रो सेवाएं बहाल हुईं। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए ट्रेन में एक-एक सीट छोड़ने के नियम लागू किया गया। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने सरकार से आग्रह किया है कि डीटीसी बसों की तर्ज पर सभी सीटों पर यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाए। इस पर मंजूरी मिलते ही मेट्रो सेवाएं लॉकडाउन से पहले की स्थिति में आ जाएंगी। मेट्रो सेवाएं बहाल होने के बाद से कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग चल रहे हैं।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ.मंगू सिंह का कहना है कि स्टेशनों पर भीड़ न होने देने का भी ध्यान रखा जा रहा है। अब अधिक से अधिक यात्रियों को सफर का मौका देने के लिए डीटीसी बसों की तर्ज पर मेट्रो में भी राहत मांगी गई है। स्टेशन पर भीड़ न होने देने के लिए एक या दो एंट्री-एक्जिट गेट ही खोले गए हैं। यात्रियों के प्रवेश में भी अंतराल रखा जा रहा है। मेट्रो सेवाएं बहाल होने पर यात्रियों की संख्या एक तिहाई रह गई थी।

डीएमआरसी प्रबंध निदेशक का कहना है कि ऑफ पीक ऑवर के दौरान भी मेट्रो की फ्रिक्वेंसी कम करने के बजाय बढ़ाई गई, ताकि यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में दिक्कत न आए। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर दो नए एस्कलेटर शुरू किए हैं। यहां अब इनकी संख्या 47 हो गई है। 3 मेट्रो लाइनों रेड, येलो और वॉयलेट के यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा है। डीएमआरसी ने बताया कि मंगलवार को कश्मीरी गेट, रेड लाइन पर रिठाला, ब्लू लाइन पर उत्तम नगर (पूर्व), नवादा, राजौरी गार्डन, शादीपुर, यमुना बैंक, सुभाष नगर और आरके आश्रम पर नए एस्कलेटर शुरू किए हैं।

दुर्गेश पाठक ने शालीमार बाग में प्रत्याशी सुनीता मिश्रा के समर्थन में पद यात्रा की

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने बुधवार को शालीमार बाग में प्रत्याशी सुनीता मिश्रा के समर्थन में पद यात्रा की। दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुनीता मिश्रा को मतदाताओं ने जबरदस्त समर्थन दिया है और भाजपा को एमसीडी से बाहर निकाल फेंकने का दावा किया। दिल्ली की जनता के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी जनता की सभी समस्याओं को दूर करेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शालीमार बाग- नॉर्थ 62एन वार्ड से प्रत्याशी सुनीता मिश्रा के लिए आज पद यात्रा की। इस दौरान उन्होंने जन संवाद किया। पद यात्रा के दौरान शालीमार निवासियों का पूरा जन सैलाब देखने को मिला। जनता के बीच हर्ष-ओ-उल्लास का माहौल सुनीता मिश्रा के लिए जबरदस्त समर्थन जताया है। नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की खुलकर निंदा की और इस बार एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने की बात कही है। हम दिल्ली की जनता के साथ हैं और उनके हित में हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि शालीमार बाग में पद यात्रा कर वहां के लोगों के साथ जनसंवाद किया। पद यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों के बीच खुशी का माहौल था। हमने उनसे आने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के माध्यम से जनता के साथ जो अन्याय किया है, उससे जनता को छुटकारा दिलाने का वादा किया।

पुलिस इंस्पेक्टर संजय चौहान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कोविड-19 का वैक्सीन लेते हुए।

पूर्व कर्मचारी ने ज्वेलर से मांगी 50 लाख रंगदारी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में ज्वेलर को सबक सिखाने के लिए पूर्व कर्मचारी अजय (25) ने 50 लाख रु रंगदारी मांग ली। जांच के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया तो अजय ने खुलासा किया कि शोरूम की मैनेजर से उसकी दोस्ती थी। पता चलने पर ज्वेलर ने महिला को निकाल दिया। इसके गुस्से में अजय ने भी नौकरी छोड़ दी। ज्वेलर ने महिला को दोबारा रख लिया तो उसे ज्वेलर से उसकी गहरी नजदीकी का शक हुआ। इसके बाद कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उसने रंगदारी मांगी, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त दीपक यादव का कहना है कि 4 जनवरी को जेवर महल शोरूम के मालिक जितेंद्र ने प्रीत विहार थाने में 50 लाख रुपये रंगदारी मांगे जाने की शिकायत दी थी। उनके सिक्योरिटी गार्ड को एक ऑटो चालक रंगदारी की मांग का पत्र दे गया था। जांच में पता चला कि एक युवक ने चोट लगने की बात कह ऑटो चालक से पत्र गार्ड तक पहुंचाने को कहा था। पुलिस ने मौजूदा व पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ की। एक साल पहले नौकरी छोड़ने वाला पूर्व कर्मचारी अजय घर से गायब मिला। मंगलवार सुबह उसे शाहदरा के स्वामी दयानंद अस्पताल शाहदरा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ में रंगदारी मांगने की बात कबूल करने के बाद अजय का कहना है कि वह क्लब जाने, महंगे कपड़े पहनने और हाईफाई जीवन शैली का शौकीन है। मालिक ने उससे दोस्ती रखने के कारण महिला मैनेजर को निकाला तो उसे गुस्सा आ गया। उसने भी नौकरी छोड़ दी। मैनेजर को दोबारा नौकरी पर रखा गया तो उसे मालिक पर महिला से नजदीकी का शक हुआ। उसने बदला लेने के लिए रंगदारी मांगी।

पीएम मोदी के बयान के बाद प्रदर्शनकारियों के रुख में आई नरमी

नई दिल्ली । तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर दिल्ली-एनसीआर में शाहजहांपुर, टीकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना-प्रदर्शन मंगलवार को 76वें दिन प्रवेश कर गया। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों से वार्ता से प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने सार्थक रूप में लिया है। मोर्चा की समन्वय समिति के सदस्य शिव कुमार शर्मा कक्काजी का कहना है कि केंद्र सरकार वार्ता का स्थान और तारीख तय करे, किसान सरकार से वार्ता को फिर तैयार हैं। शिव कुमार शर्मा कक्काजी ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहा कि किसान वार्ता से कभी पीछे नहीं हट रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की बात सिर्फ मौखिक रूप में कर रहे हैं। यह एक तरह से जबानी जमा खर्च है, जिसकी लिखित कानूनों के सामने कोई अहमियत नहीं है। इसलिए किसान संगठन भी मौखिक

रूप में ही प्रधानमंत्री के बयानों का स्वागत कर रहे हैं।

बता दें, तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड से पहले किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई 11वें दौर वार्ता भी बेनतीजा रही थी। इसके बाद यह माना जा रहा था कि दोनों तरफ से वार्ता के दरवाजे बंद हो गए हैं मगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मन की बात और अब राज्यसभा में दूसरी बार वार्ता का खुला आमंत्रण दिया है।

इसके बाद किसान संगठन भी बैकफुट पर आ गए हैं। किसान संगठन भी यह संदेश किसानों के बीच नहीं जाने देना चाहते कि वार्ता को लेकर किसान संगठन अड़ियल रुख अपना रहे हैं।

वहीं, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डा. दर्शनपाल ने कहा कि वह भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसके लिए अधिकारिक तौर पर न्योता आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांग सरकार के पास पहले ही रख चुके हैं। उनकी ओर से बातचीत का प्रस्ताव तैयार है। सरकार को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए।

संपादकीय

कोरोना पर काबू

कोरोना वायरस से लड़ने में भारत की दिखती कामयाबी जितनी सुखद लग रही है, उतनी ही उत्साहजनक भी है। भारत में अभी 60 लाख लोगों को भी कोरोना टीका नहीं लगा है, लेकिन तब भी कोरोना संक्रमण का काबू में आते दिखना अनायास ही आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में एक समय वह भी था, जब लगभग हर दिन देश में एक लाख से ज्यादा कोरोना मामले मिल रहे थे। अब प्रतिदिन करीब दस हजार मामलों का सामने आना एक महत्वपूर्ण संकेत है। आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो 130 करोड़ की आबादी वाला विशाल भारत कोरोना मामलों को न्यूनतम स्तर पर ले आया है। सितंबर के बाद गिरावट का क्रम शुरू हुआ और अब जो स्थिति है, वह वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। भारत में जब कोरोना ने गति पकड़ी थी, तब पूरी दुनिया में चिंता थी कि भारत अपने कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के साथ कैसे मुकाबला करेगा। हम कोरोना संक्रमण में लगभग शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन आखिर क्या हुआ कि यहां कोरोना सिमटने लगा? अब देखना है कि जैसे कोरोना परिवार की अन्य बीमारियां सार्स और मर्स अचानक गायब हो गईं, क्या कोरोना भी अचानक गायब हो सकता है? वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में न तो कोरोना जांच कम हुई है और न सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी। फिर भी मरीजों की संख्या कम हुई है और अब अस्पताल भी दबाव में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य मरीजों का भी इलाज शुरू हो गया है। ऐसे अनेक संस्थान और वैज्ञानिक हैं, जो भारत में कोरोना की पड़ताल कर रहे हैं, इसमें यह जानने की कोशिश भी शामिल है कि भारत ने कोरोना को काबू में करने के लिए क्या-क्या किया? यह बिल्कुल सही है कि भारत में ऐसे बहुत से इलाके हैं, जहां कोरोना दिशा-निर्देशों की पालना कड़ाई से की गई है, लेकिन बहुत विशाल क्षेत्र ऐसा भी है, जहां पर लोगों ने कोरोना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। गनीमत रही कि महानगरों की तरह कोरोना गांवों में नहीं फैला। सवाल है कि क्या शहर में रहने वाले लोगों की तुलना में गांव में रहने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बेहतर होती है? क्या उन इलाकों में कोरोना ने ज्यादा आतंक फैलाया, जो तुलनात्मक रूप से विकसित या कुछ संपन्न थे? कोरोना के अनुभवों के बाद भारत में सुरक्षित जीवन शैली को लेकर भी अध्ययन जरूरी हैं। जिन इलाकों में कोरोना नहीं फैला और जिन इलाकों में खूब फैला, दोनों ही जगह गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। भारत की जलवायु को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ठंडी और शुष्क जगहों पर वायरस हवा में ज्यादा देर तक सक्रिय रहता है। गरम हवा और नमी वाली जगहों पर वायरस ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाता। बंद जगहों की अपेक्षा खुली जगह ज्यादा सुरक्षित है। एक बड़ी वजह भारत में युवाओं की आबादी भी है। भारत में आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है और महज छह प्रतिशत आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। तो भारत की अच्छी भौगोलिक स्थिति और आबादी, दोनों पर अध्ययन जरूरी है, ताकि भारत को सेहतमंद बनाया जा सके। कुछ और दिन की सावधानी से भारत कोरोना को काबू में कर लेगा और शायद ज्यादातर लोगों को टीकाकरण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

अनिवार्यता को प्रोत्साहन

केंद्र सरकार देश में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। नई नीति के फायदे गिनाते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि नई नीति के तहत जो वाहन स्वामी अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को 'स्क्रैप' (कबाड़) करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें नये वाहन की खरीदारी में अनेक लाभ दिए जाएंगे। वाहन निर्माता खरीदारों को ये लाभ देंगे। गौरतलब है कि बजट 2021-22 में 'स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति' की घोषणा की गई है। इस कबाड़ नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में 'फिटनेस टेस्ट' होगा। दरअसल, रिसर्च से पता चला है कि चार सीटों वाले एक पुराने सेडान वाहन पर पांच साल में 1.8 लाख रुपये का नुकसान होता है, वहीं भारी वाहनों पर इससे तीन साल में 8 लाख रुपये का नुकसान होता है। माना जा रहा है कि नई नीति से वाहन उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी। वाहन उद्योग के हालात बेहतर होंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वाहन उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महद्मवपूर्ण क्षेत्र है। अनुमान लगाया गया है कि प्रोत्साहक किस्म की इस नीति से आने वाले वर्षों में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। न केवल यह फायदा, बल्कि पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिल सकेगी। गड़करी के मुताबिक, जल्द ही कबाड़ नीति संबंधी ब्योरे जारी किए जाएंगे। आम तौर पर नई नीति को लेकर लोग ज्यादा उत्साहन नहीं दिखाते। ऐसे में सरकार चाहती है कि अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को कुछ प्रोत्साहन मिले। अलबता, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति का अनुपालन अनिवार्य होगा। लोग कबाड़ का विकल्प खुद से चुनें इसके लिए हरित कर और अन्य तरह के शुल्कों का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। चूंकि परीक्षण में मानव हस्तक्षेप नहीं होगा इसलिए भ्रष्टाचार या आंकड़ों में हेराफेरी की गुंजाइश नहीं होगी। कह सकते हैं कि अपने वाहनों को स्वेच्छा से कबाड़ घोषित नहीं कराने वालों को हतोत्साहित करने के तमाम उपायों के साथही प्रोत्साहन देने के प्रयास भी इस नीति में हैं।

प्रवीण कुमार सिंह

हाय उफ्फ 443 दिन

मोबाइल में मैसेज आया उस वस्त्र कंपनी का, आशय था कि हाय आप 443 दिनों से कुछ खरीदने हमारी वेबसाइट पर ना आए।
कोई तो मिस करता है आपको, यह पता लगता है तो बंदे की निगाह में अपनी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। तकनीक ने बहुत खेल कर दिए हैं, 443 दिनों से ना गया उस वेबसाइट पर, उस कंपनी को मालूम है। पत्नी, प्रेमिका भी इस स्तर का कैलकुलेशन ना रखती कि आखिरी बार आपने आई लव यू 564 दिनों पहले बोला था। सही है जी। धंधा करने वालों से बड़ा प्रेमी कोई ना होता।
कोई है जो मिस करता है। हिंदी लेखक को आम तौर पर सितम्बर के हिंदी दिवस के आसपास मिस किया जाता है, भाव यही रहता है कि बुला लाओ किसी हिंदी वाले को शाल वगैरह देकर निपटाएं। हिंदी दिवस के अलावा हिंदी के लेखक मिस ना किया जाता। दिनों की गिनती बताकर मिस कर रहा है कोई। तकनीक इस कदर मारक हो गई है कि कोई नासमझ हो तो खुद को वीआईपी टाइप समझने लगे। यह समझने लगे कि हम कितने बड़े और महद्मवपूर्ण कस्टमर हैं उस कंपनी के, हमको मिस करते हैं कंपनी वाले। कोई किसी को मिस ना करता, धंधे को मुनाफे को मिस करते हैं, तो हमें मिस कर लेते हैं, यह ज्ञान ही सत्य है। पर इस सच को समझने से बंदे की वैल्यू खुद की निगाह में गिर जाती है।
हमारी औकात तब ही है, जब तक हम खरीदते हैं। बंदे को कोई मिस ना करता ग्राहक को मिस करते हैं, यह बाजार का, दुनिया सत्य है। मेरी बर्थ डे पर वो इंश्योरेंस कंपनियां मेल के जरिए हैप्पी बर्थडे बोलती हैं, जिनसे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। शादी के पांच सात साल बाद तो पत्नी भी बर्थडे पर शुभकामनाएं ना देती, इंश्योरेंस कंपनियां क्यों दे रही हैं।
कोई दिल पे ना ले, तकनीकी मामला है, सब रिकॉर्ड में होता है, मशीन ही भेज देती है हैप्पी बर्थडे। वैसे इंश्योरेंस कंपनियों के हैप्पी प्रॉफिट तब ही मोटे होते हैं, जब तक ग्राहक हैप्पी बर्थडे मनाकर जीवित रहे। ग्राहक निकल ले, तो क्लेम देना पड जाता है।

सड़क पर गड़ी कीलों का संदेश

कुछ चाक्षुष अनुभव ऐसे होते हैं, जिन्हें आप हमेशा भूल जाना चाहेंगे। किसान आंदोलन के दौरान हाल में उन्हें और उनके ट्रैक्टरों को राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा सड़कों पर गाड़ी गई लंबी नुकीली कीलें या कंसरटीना तारों के बाड़े ऐसे ही दृश्य हैं, जिन्हें देखते हुए वितृष्णा और दहशत एक साथ पैदा होती हैं। यह क्यों संभव हो रहा है कि लोकतंत्र बनने की प्रक्रिया में लगे एक समाज और अपने को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही पुलिस की जुगलबंदी ऐसे दृश्य निर्मित कर रही है, जो किसी भी सुसंस्कृत आंखों को रुचिकर नहीं लगेंगे।
इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भारत में पुलिस की प्रतिक्रियाएं अक्सर गैर-पेशेवर कारणों से प्रभावित होती हैं। 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली में घुसे अराजक ट्रैक्टर सुरक्षा चक्र तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और बिना किसी बड़ी बाधा के उस पर एक धार्मिक झंडा फहरा दिया गया, उससे किसी को भी दिल्ली पुलिस को एक पेशेवर पुलिस बल मानने में दिक्कत होगी। अपनी शुरुआती नालायकी पर लीपापोती करने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के अगले चरण को रोकने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ऐसे इंतजामात किए कि कई सांसदों को सदन में कहना पड़ा कि ऐसे दृश्य तो उन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर भी नहीं देखे हैं। पुलिस की हड़बड़ी में की गई अतिरेकी व्यवस्थाओं के कारण तलाशना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व एक स्थिति के बाद पुलिस के नेतृत्व पर छोड़ दिया जाना चाहिए। किसी परिस्थिति में लक्ष्य निर्धारित होने के बाद उसे हासिल करने की रणनीति बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी इसी नेतृत्व की होनी चाहिए, पर ऐसा बिरले ही होता है। अमूमन पुलिस द्वारा तय की गई रणनीति में महत्वपूर्ण सुझाव गैर-पेशेवर सूत्रों से आते हैं और अक्सर वही अंतिम भी होते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में फैली अराजकता इसी का उदाहरण है। जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, उससे विश्वास करना मुश्किल होगा कि किसान मार्च से निपटने की रणनीति पुलिस का शीर्ष नेतृत्व बना रहा था या उसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर रहा था। पूरा देश दम साधे दिल्ली की सड़कों पर अराजकता और उससे निपटने में पुलिस की असफलता देख रहा था। यह सही है कि गणतंत्र दिवस के आयोजनों की विराटता और उन पर संभावित आतंकी खतरों के चलते दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता वही थी, पर इसके बाद भी जितने संसाधन उसके पास दिख रहे थे, वे दृढ़ता से और सही रणनीति से इस्तेमाल किए जाते, तो अराजकता काफी हद तक सीमित की जा सकती थी। छोटे परदे से चिपका देश दोनों पक्षों, किसानों और पुलिस के घात-प्रतिघात देख रहा था और किसी से यह छिपा नहीं रहा कि पुलिस कभी भी स्पष्ट नहीं थी कि उसे करना क्या है। कोई अदृश्य हाथ था, जो उसकी रणनीति में अपनी जरूरत के मुताबिक वक्ती बदलाव कर रहा था। नतीजतन, लाल किले में जो कुछ हुआ, उसके लिए कोई तैयार नहीं था। 26 जनवरी की असफलता के दौरान इस संयम के लिए तो दिल्ली पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए कि अपने कर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने उपद्रवियों पर गोली नहीं चलाई और किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ, पर इस सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिलता कि आंसू गैस के गोलों व लाठीचार्ज के बाद उनके पास रबर बुलेट जैसे कम घातक विकल्प क्यों नहीं थे, जिनके चलते बिना जान लिए भी भीड़ को विसर्जित किया जा सकता था? पुलिस के पास स्टन ग्रिनेड या मिर्चों के छिड़काव जैसे विकल्प ज्यादा होने चाहिए, जो जान लेने की जगह भय उत्पन्न करें। इसके बाद 6 फरवरी के चक्का जाम के दौरान जिस तरह की नाकाबंदी दिल्ली सीमा पर की गई, वह किसी पेशेवर कार्रवाई से अधिक अपनी पिछली असफलता की खीझ निकालने का प्रयास अधिक लगता है। एक खराब आप्टिक की तरह बड़ी-बड़ी नुकीली कीलें सड़क पर गाड़ी गईं, रास्तों पर कंक्रीट के टुकड़े रखे गए या कंसरटीना तार बिछाए गए। हम यह भूल गए कि अब एक विश्व ग्राम में तब्दील दुनिया में जनांदोलनों से निपटने के लिए की जाने वाली राज्य की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय खुर्दबीन से होकर गुजरती है। मानवधिकारों का एक आम स्वीकृत स्तर है, जिसकी कसौटी पर कसने पर इन तस्वीरों से भारत की छवि धूमिल होगी और जिस तरह की अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं इन पर मिलीं, वे किसी भी तरह से उत्साह बढ़ाने वाली नहीं थीं।
थोड़े धैर्य और कल्पनाशीलता से काम लिया जाता, तो इन्हीं उपायों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता था। मसलन, कीलों जड़ें लकड़ी के फट्टे सुरक्षित रखे जा सकते थे और जिन्हें जरूरत पड़ने पर किसी भी रास्ते पर तेजी से लगाया जा सकता था। इसी तरह कंसरटीना तार भी प्रशिक्षित टुकड़ी द्वारा समय रहते बिछाया जा सकता है। किसान कोई शत्रु देश के सैनिक नहीं हैं, जो रात के अंधेरे में अचानक हमला करेंगे। हर आंदोलन पूर्व घोषित होता है और पुलिस के अवरोध तोड़ने के पहले घंटों खींचातानी चलती है। हर बार इतना समय तो होता ही है कि पुलिसकर्मी जरूरत पड़ने पर उपरोक्त अवरोधक लगा सकें। यह सब नहीं किया गया और दिल्ली सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसा दिखने दिया गया, तो शायद इसके पीछे वह उतावली झुंझलाहट थी, जिसके लिए किसी पेशेवर पुलिस बल में जगह नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन का क्या नतीजा निकलेगा, इसका दारोमदार तो राजनीतिक नेतृत्व पर है, पर आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, इसकी कुछ हद तक जिम्मेदारी पुलिस बलों की भी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को अलग-अलग और एक साथ भी बैठकर इस पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने आवश्यक मात्रा में बल प्रयोग नहीं किया और बिना जरूरत उन उपकरणों का प्रदर्शन किया, जिनसे मानवाधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र का हमारा दावा निश्चित रूप से कमजोर पड़ा है । राजनीतिक नेतृत्व को भी इस तरह की परिस्थितियों में पुलिस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराने के साथ-साथ उन्हें फैसलों में पर्याप्त स्वतंत्रता देनी ही होगी, तभी संभव हो सकेगा कि समय पर पर्याप्त बल का प्रयोग हो और बेजरूरत उनका फूहड़ प्रदर्शन न किया जाए। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

> यह क्यों संभव हो रहा है कि लोकतंत्र बनने की प्रक्रिया में लगे एक समाज और अपने को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही पुलिस की जुगलबंदी ऐसे दृश्य निर्मित कर रही है, जो किसी भी सुसंस्कृत आंखों को रुचिकर नहीं लगेंगे।

चमोली का हादसा

ग्लेशियरों को बचाने की मुहिम चले

उत्तराखण्ड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से विष्णु प्रयाग से ऊपर अलकनंदा की सहयोगिनी धौलीगंगा का बांध बह गया। इससे हुई तबाही से समूचे उत्तराखण्ड में हाहाकार मचा है। असलियत में ग्लेशियर फटने के बाद पानी के दबाव से धौलीगंगा का बांध टूटा, जिससे धौली नदी में बाढ़ आ गई। तपोवन रैणी स्थित ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बैराज पूरी तरह ध्वस्त हो गया। बांध टूटने और फिर धौली नदी की बाढ़ से चारों ओर तबाही का मंजर पैदा हुआ। समीपस्थ गांवों का शेष दुनिया से संपर्क टूट गया है। चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ-मलारी पुल ढह गया है।
सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन द्वारा घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है। बारिश और पारा गिरने से भीषण ठंड से राहत कार्य में रुकावट आ रही है लेकिन जवान विषम हालात में भी तपोवन में राहत कार्य को अंजाम दे रहे हैं।
वैज्ञानिक इस घटना को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे हैं। वह बरसों से चेता रहे हैं कि समूची दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर लगातार पिघलकर खत्म होते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट, बीते 5 दशकों से लगातार गर्म हो रही है। नतीजतन आस-पास के हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। यह भी सच है कि वह चाहे हिमालय के ग्लेशियर हों या तिब्बत के या फिर आर्कटिक ही क्यों न हो, वहां बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है।
एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन सबूत हैं कि बढ़ते तापमान के चलते हिमालय के तकरीबन साढ़े छह सौ से अधिक ग्लेशियरों पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। उनकी पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ के अनुसार भारत, नेपाल, भूटान और चीन में तकरीबन दो हजार किलोमीटर के इलाके में फैले 650 से ज्यादा ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार पिघल रहे हैं। वर्ष 1975 से 2000 के बीच जो ग्लेशियर हर साल दस इंच की दर से पिघल रहे थे, वह 2000 से 2016 के बीच हर साल बीस इंच की दर से पिघलने लगे।

बीते बरसों में डॉ. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उसने सरकार को सिफारिश की कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक अध्ययन के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन और आधारभूत ढांचा मुहैया कराये जाने की बेहद जरूरत है। साथ ही यहां पर्यटन की गतिविधियों को भी नियंत्रित किया जाना बेहद जरूरी है। आईपीसीसी दस साल पहले यह चेता चुकी है कि हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर 2035 तक और आइसलैंड के सभी ग्लेशियर आने वाले 200 सालों में ग्लोबल वार्मिंग के चलते खत्म हो जायेंगे। अब यह स्पष्ट है कि हिमालय के कुल 9600 के करीब ग्लेशियरों में से तकरीबन 75 फीसदी ग्लेशियर पिघल कर झरने और झीलों का रूप अख्तियार कर चुके हैं। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो बर्फ से ढकी यह पर्वत श्रृंखलाएं आने वाले कुछ सालों में बर्फ विहीन हो जायेंगी।
यह सब हिमालयी क्षेत्र में तापमान में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ-साथ अनियोजित विकास का परिणाम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के जंगलों में लगी आग से निकला धुआं और कार्बन से ग्लेशियरों पर एक महीन-सी काली परत पड़ रही है। यह कार्बन हिमालय से निकलने वाली नदियों के पानी के साथ बहकर लोगों तक पहुंच रहा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गर्म हवाओं के कारण इस क्षेत्र की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के अलावा मानवीय गतिविधियां और जरूरत से ज्यादा प्रकृति का दोहन भी ग्लेशियरों के पिघलने का एक बड़ा कारण है।
हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा तकरीबन 10,000 ग्लेशियर हैं। अकेले उत्तराखण्ड में 900 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। यह अब किसी से छिपा नहीं है कि ग्लेशियर दिनों-दिन तेजी से पिघलने से झीलों के बनने की दर में भी बढ़ोतरी होगी जो भयावह खतरे का संकेत है। यह अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा भी आयेगा जब पेयजल समस्या तो भयावह रूप धारण कर ही लेगी, पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए जहां बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से प्राथमिकता के आधार पर लड़ना बेहद जरूरी है, वहीं ग्लेशियर से बनी झीलों से उपजे संकट का समाधान भी बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक डॉ. डी.पी. डोभाल कहते हैं कि यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो हिमालय के एक-तिहाई ग्लेशियरों पर मंडराते संकट को नकारा नहीं जा सकता। इससे पहाड़ी, मैदानी इलाके के 30 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों पर भारत, चीन, नेपाल और भूटान की कमोबेश 80 करोड़ आबादी निर्भर है। इन नदियों से सिंचाई, पेयजल और बिजली का उत्पादन होता है। यदि यह पिघल गए, उस हालत में सारे संसाधन खत्म हो जायेंगे और ऐसी आपदाओं में बढ़ोतरी होगी।

सरकारों की सांप्रदायिक भाषा

देशभर के किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि उत्पाद कानूनों के खिलाफ 26 नवम्बर से राजधानी दिल्ली के चारों तरफ लाखों की तादाद में घेराव किए हुए हैं।
अब सरकार ने 88 पृष्ठों की एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है-प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, सिखों के साथ विशेष संबंध। पुस्तिका में मोदी सरकार सिख धर्म में आस्था रखने वालों को याद दिला रही है कि उसने कैसे सिखों के धार्मिक सवालों का सम्मान किया है। संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को किसान अपने भविष्य के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सरकार सिख धर्म मानने वालों के साथ अपने रिश्तों की याद क्यों दिला रही है?
भारतीय राजनीति का खास तौर से सत्ताधारी दलों के लिए धर्म ही एक औजार बचा है, जिसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सवालों को खतरनाक दिशा की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सिख धर्म और मोदी सरकार के रिश्ते पर पुस्तिका छापने से पहले जब किसान दिल्ली के चारों तरफ प्रदेशों की सीमाओं पर पहुंच गए तो उनके बीच 'खालिस्तान' समर्थकों के आरोप को बढ़-चढ़कर प्रचारित किया गया। इससे पहले 2019 के दिसम्बर महीने में संसद ने नागरिकता कानून में बदलाव किया था और उसे संविधान के विरुद्ध बताया जा रहा था तब भी उस कानून के विरोध में होने वाले आंदोलन को मुस्लिमों के आंदोलन के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया गया था। सरकार द्वारा नागरिकता कानून के जरिए संविधान के मूल चरित्र पर चोट पहुंचने की दलीलें पेश की गई और इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन शुरू हुए, लेकिन उस आंदोलन को मुस्लिमों के विरोध के रूप में पेश किया गया। सत्ताधारी दल द्वारा धर्म को राजनीतिक दलों द्वारा इस्तेमाल करने का यह सच इतना साफ है कि वह प्रवृत्ति नई आर्थिक व्यवस्था के बनाने की योजना में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लगे बहुत सारे दलों में साफ दिखाई देती है। इसके भी तथ्य सामने आ सकते हैं कि प्रवृत्ति ब्रिटिश सत्ता विरोधी आंदोलनों में भी देखी गई हो।

प. बंगाल में 2007 में जब वाम मोर्चे की सरकार थी तब नंदीग्राम में कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध देशव्यापी असर पैदा करने वाला आंदोलन साबित हुआ। नंदीग्राम के इलाके में मुस्लिम किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते दिख रहे थे। सरकार द्वारा जोर जबरदस्ती पर 14 नवम्बर, 2007 को कोलकाता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम नाम के बैनर लगाकर किसानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाइयों का विरोध किया गया, लेकिन उसके साथ बांग्लादेश में जन्मी लेखिका तसलीमा नसरीन का वीजा रद्द करने की मांग जोड़ दी गई। प. बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी जो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि पर किसी तरह का दाग नहीं होने का दावा करती थी, लेकिन उसने नंदीग्राम में विरोध को स्वीकार करने के बजाय तसलीमा को राज्य से बाहर करने का फैसला तत्काल कर लिया। वाम मोर्चे सरकार के इस फैसले का लगभग पांच सालों के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किस तरह इस्तेमाल किया, यह भी दिलचस्प है। केंद्र में मनमोहन सिंह की अल्पमत वाली सरकार थी और वाम मोर्चा का उसे समर्थन था। हुआ यह कि अमेरिकी झुकाव वाले मनमोहन सिंह अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करना चाहते थे। वाम मोर्चा अमेरिकी परमाणु समझौते का विरोधी था। वाम मोर्चा ने मनमोहन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब कांग्रेस के प्रवक्ता ने 5 फरवरी, 2013 को बताया कि वाम मोर्चा सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार के तसलीमा के भारत में ठहरने के वीजा की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया था जिसकी वजह से वीजा पर केंद्र सरकार का फैसला कई महीनों तक टला था।
भारतीय राजनीति में यह एक दिलचस्प खेल चलता है कि हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक विचारधारा धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यकों की तरफ झुकाव रखने वाली और हिंदुओं के विरोध वाली विचारधारा बताकर सांप्रदायिकता के रूप में पेश करती है। साथ ही, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर जनतांत्रिक और संवैधानिक विरोध को भी सांप्रदायिक करार देने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, उनके बीच भी जब मौका होता है तब वे एक दूसरे के खिलाफ सांप्रदायिक होने या सांप्रदायिकता की तरफ झुकने का आरोप लगाते हैं। जब तक ऐसे दलों के बीच साथ-साथ रहने का समझौता होता है, तब तक वे एक दूसरे के लिए धर्मनिरपेक्ष होते हैं। साथ छूटते ही एक दूसरे के लिए सांप्रदायिक हो जाते हैं। सांप्रदायिकता के विरोध को राजनीतिक दल अपने संबंधों के लिए आधार मानते रहे हैं।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

अब्दुल हमीद वार्ड में बोरिंग से क्षेत्रीयजनों को मिलेगी राहत

जबलपुर। अब्दुल हमीद वार्ड कमला भंडार के पीछे कटरा खेरमाई रोड पर बोरिंग का कार्य किया जा रहा है। इससे क्षेत्रीयजनों को स्वच्छ जल की सुविधा मिलेगी। उपरोक्त जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पार्षद ताहिर अली की ओर से बताया गया कि 2 बोरिंग राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा दिए गए फंड एवं विधायक लखन घनघोरिया की अनुसंशा से कराए जा रहे हैं। वार्ड के कमला भंडार के पीछे कटरा खेरमाई रोड पर मूर्तिकार विजय वर्मन के बाजू से बोरिंग करवाई गई, जिससे आने वाले गर्मी के दिनों में लोगो को भरपूर पानी मिलेगा। इस अवसर पर कोमल रैकवार, जग्गू केसरवानी, प्रहलाद , मुकेश, सुनील तिवारी, मुकेश तिवारी, विजय बर्मन, राकेश लखेरा, ललित तिवारी, नीरज पटेल, सुंदरम पटेल, छोटू आदि उपस्थित रहे।

आरडीयू में वार्षिक बजट की बैठक का हुआ आयोजन

जबलपुर। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र की अध्यक्षता, प्रभारी कुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा एवं वित्त नियंत्रक रोहित सिंह कौशल की उपस्थिति में यूनिवर्सिटी के आगामी वार्षिक बजट पर विस्तृत चर्चा हेतु संकायाध्यक्षों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में आय में वृद्धि हेतु आय के संभावित स्रोतों एवं संभावित व्यय पर चर्चा की गई। बैठक में संकायाध्यक्षों में प्रो. राकेश बाजपेयी, प्रो. रामशंकर, प्रो. सुरेन्द्र सिंह एवं प्रो. धीरेन्द्र पाठक तथा सहायक कुलसचिव अभयकांत मिश्रा, इंजी. विनोद जारोलिया, वित्त शाखा के प्रेम प्रकाश पुरोहित, के.के. दुबे एवं भण्डार विभाग के ओ.पी. यादव आदि उपस्थित रहे।

भारत कृषक समाज ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

सरकार नहीं किसान बताएंगे कृषि कानूनों में कहां है 'काला'

पत्रकारवार्ता में किसानों की ओर से उठाए सवाल

जबलपुर , (एजेंसी)।

देश के कृषि मंत्री संसद में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि कृषि कानून में काला क्या है। तो देश के किसान इस बात को विस्तार से बताएंगे कि कृषि कानूनों में किन-किन बिन्दुओं पर सरकार की नियत कितनी 'काली' है। पिछले लगभग तीन माह से अधिक समय से किसान संगठनों के नेतृत्व में हजारों किसान काले कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों में शामिल किसान विरोधी बातों को लेकर अब महाकौशल एवं प्रदेश के सभी स्थानों पर आम किसानों को जागरूक किया जाएगा। उपरोक्त वक्तव्य किसान नेताओं ने बुधवार को भारत कृषक समाज की ओर से आयोजित पत्रकारवार्ता में व्यक्त किए। पत्रकारवार्ता में भारत कृषक समाज संभागीय सचिव रूपेन्द्र पटैल ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, इसपर सवाल यह है कि एक-दो नहीं लाखों की संख्या में किसान इतने लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कोई किसी को भड़काकर कितने समय तक सड़कों पर बैठाया जा सकता है। पत्रकारवार्ता में किसान नेताओं ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर तरह-तरह के आरोप लगाना, उन्हें रोकने सड़कें खोदना, रास्ते में कीलें बिछाना, कंटीले तार की बाड़ लगाना, दिल्ली की भरी ठंड में पानी की बौछारें छोड़ना सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हैं।

इस प्रकार होंगे जागरुकता कार्यक्रम

पत्रकारवार्ता में किसान नेताओं की ओर से बताया गया कि आगामी दिनों में प्रदेशभर में सरकार को सद्बुद्धि देने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास कार्यक्रम, प्रार्थना सभा के साथ किसानों के पक्ष में कविता, पोस्टर्स प्रदर्शन, जनगीतों का गायन, किसानों के पक्ष में चित्रकला प्रदर्शनी तक के आयोजन कर किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। पत्रकारवार्ता में भारत कृषक समाज के जय सिंह गायकवाड़, ठा. विक्रम सिंह, संजय जैन, प्रमोद शुक्ला, रमेश पटैल, मुकेश पटैल, मुन्ना मरावी, परमलाल अहवासी, मनीष राय, भानु यादव, अर्जुन पटैल, गोकुल पटैल, अरविंद सिंह आदि उपस्थित रहे।

पत्रकारवार्ता में भारत कृषक समाज के एड. रमेश पटैल ने बताया कि कृषि कानूनों कई बिन्दुओं पर किसानों ने विरोध जताया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

- कान्ट्रेक्ट फार्मिंग में विवाद होने पर, सिविल कोर्ट में वाद दायर करने के न्यायिक अधिकार से किसानों को वंचित रखा गया है।
- निजी क्षेत्र की मंडी को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
- सरकार खुद तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदे और निजी मंडियों को,अपनी मनमर्जी से खरीदने की अंकुश विहीन छूट दे रही है।
- किसी को भी जिसके पास पेन कार्ड हो, उसे किसानों से फसल खरीदने की छूट देना किसानों को मंजूर नहीं है।
- जमाखोरी के अपराध को वैध बनाए जाने का कुत्सित प्रयास है।

कटनी व दमोह के वार्ड आरक्षणों को चुनौती देने वाले मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

विधायक संदीप जयसवाल का जवाब देने अंतिम मोहलत, अगली सुनवाई 23 को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में कटनी व दमोह नगर निगम के वार्ड आरक्षण को चुनौती देते हुए दायर अलग-अलग मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस मोह रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई दौरान पाया कि मामले में सरकार ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन विधायक की ओर से जवाब नहीं पेश किया गया। जिस पर युगलपीठ ने कटनी विधायक संदीप जयसवाल को जवाब के लिये अंतिम अवसर देते हुए मामलों की सुनवाई 23 फरवरी को निर्धारित की है

उल्लेखनीय है कि यह जनहित का मामला कटनी निवासी भोला चक्रवर्ती की ओर से दायर किया गया है। वहीं वार्ड आरक्षण को लेकर कटनी के ही रमेश सोनी व कांग्रेस नगराध्यक्ष मिथलेश जैन की ओर से भी मामले दायर किये गये थे। वहीं दमोह के वार्ड आरक्षण को राजनारायण धुर्वे व एक अन्य की ओर से कटघरे में रखा गया था। भोला चक्रवती की ओर से दायर मामले में कहा गया है कि नगर निगम चुनाव के लिये कटनी कलेक्टर 31 जुलाई 2020 को वार्डो के आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। उस समय 45 में से 22 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये थे। जिसके बाद सत्तारूढ पार्टी के कटनी के स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल ने वार्ड आरक्षण पर आपत्ति दर्ज करने हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा।

उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण ओबीसी वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण वार्ड में बदलाव किया गया। याचिका में कहा गया है कि 10 दिसंबर 2020 को वार्ड आरक्षण का फाईनल नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसमें 45 में से 23 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिये गये, जो 50 प्रतिशत से अधिक है।

इसके साथ ही सामान्य वार्डो में रोटेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया गया। मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, उप सचिव व कमिश्नर नगरीय प्रशासन विभाग व कटनी विधायक संदीप प्रसाद जयसवाल को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त निर्देश देते हुए सभी मामलों की संयुक्त रूप से सुनवाई 23 फरवरी को किये जाने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता भोला चक्रतवी व रमेश सोनी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पैरवी की।

सहकारिता समिति में पीओएस मशीन चलाने वालों के साथ भेदभाव

पाटन। सहकारिता विभाग में समिति में पीओएस मशीन चलाने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्राप्त शिकायत के आधार पर इन्हें निकालकर उनके स्थान पर नए ऑपरेट्रो की नियुक्ति करने जा रही है। सकरा के पीओएस चलाने वाले सहायक मनीष यादव, नितिन यादव, मनीष पटेल ने बताया है कि सहायक ऑपरेटर के रूप में शासन द्वारा 2014 में नियुक्ति की गई है और इन कर्मचारियों के आधार लिंक भोपाल तक कि गई थी। पीओएस मशीन ऑपरेटर के लिए और इन्ही के द्वारा जो राशन वितरण किया जाता है। इन कर्मचारियों को समिति एवं सहकारिता से तरह-तरह के आश्वासन दिए गए थे। अब मध्यप्रदेश सरकार इन्हें अलग कर दूसरे ऑपरेटरों की भर्ती कर रही है।

बुलंदियां चाहिए तो मजबूत हो बुनियाद : हृषिकेश पांडे

मशहूर टेलीविजन कलाकार ने युवाओं को दिया संदेश

जबलपुर, (एजेंसी)। संस्कारधानी के कलाकार हृषिकेश 'ये रिश्ता क्या कहलाता' में नई भूमिका में आ रहे हैं। तिलहरी की छोटी-छोटी गलियों से निकलकर मायानगरी मुंबई में अपना अलग मुकाम बनाने वाले संस्कारधानी के कलाकार ऋषिकेश पांडे की अदाकारी अब 'ये रिश्ता क्या कहलाता' में और ज्यादा निखरकर सामने आ रही है। बीते 11 सालों से ये शो कंटीन्यू जारी है और अब हृषिकेश पांडे की उपस्थिति इसे नई ऊंचाईयों पर ले जाने का तैयार है।

गौरतलब है कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले सीरियल 'सीआईडी' के इंस्पेक्टर सचिन यानी हृषिकेश पांडे ने स्क्रीन पर अपनी दमदार आवाज और अभिनय के बलबूते एक लंबी और सार्थक अभिनय यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में लॉकडाउन के एक लंबे अंतराल के बाद पांडे अपने गृहनगर जबलपुर में पहुंचे और उन्होनें युवाओं के लिए संदेश दिया कि वह चाहे फिल्म हो या अन्य कोई कैरियर, सभी के लिये खुद को बुनियादी तौर पर मजबूत करें, क्योंकि एक अ%छी परफॉर्मेंस के लिये ये बहुत ही अहमं है। यदि चीजें सतही होंगी तो वो सुकून नहीं मिलेगा, जिसे हम कई मायनों में जीना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि हृषिकेश ने स्क्रीन पर कई पात्रों को जीवंत कर उन्हें यादगार बनाया है। कहानी घर-घर की, पिया का घर, साक्षी, कामिनी-दामिनी, दो सहेलियां, विवाह, स्पेशल ब्यूरो, सीआईडी और पोरस वे शो हैं जिनमें हृषिकेश का अलग ही अंदाज देखने को मिला है।

कोरोना के मिल 11 नए मरीज

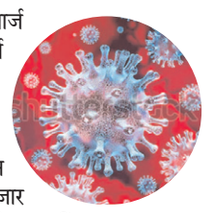

जबलपुर। कोरोना से स्वस्थ होने पर बुधवार 10 फरवरी को 17 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 877 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 11 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 17 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 15 हजार 987 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.38 प्रतिशत हो गया है । कल मंगलवार की शाम 6 बजे से आज बुधवार की शाम 6 बजे तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले 11 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 16 हजार 416 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 251 ही है । कोरोना के एक्टिव केस अब 178 रह गये हैं । कोरोना टेस्ट हेतु आज 778 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

केंट वासियों को मिली बारातघर की सौगात

जबलपुर, (एजेंसी)। केंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे चिंटू ने बताया कि छावनी परिषद के अंतर्गत कार्यकाल समाप्त होने के अंतिम दिवस परिषद के प्रयासों से आमजन के लिए हर वो सुविधा उपलब्ध कराई, जिसकी उन्हें जरूरत थी और आगे भी हम जनता की हर लड़ाई लड़ेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। कार्यकाल के अंतिम दिन भी छावनी क्षेत्र की जनता के लिए बारातघर की सौगात दी गई।

बारातघर का लोकार्पण ब्रिगेडियर संजय सज्जन्हर, केंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे चिंटू, केंट सीइओ सुब्रत पाल एवं पार्षदों द्वारा किया गया। इस मौके पर छावनी परिषद पार्षदों ने बताया कि 56 छावनियों का कार्यकाल समाप्त हो गया। 12 साल के इस कार्यकाल में छावनी परिषद जबलपुर ने केंट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे चिंटू के नेतृत्व में कई विकास कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें सदर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण, खंबताल का सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार, खेलकूद को बढ़ावा देते हुए शिवाजी मैदान का जीर्णोद्धार जैसे अनेकों विकास कीर्तिमान शामिल है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही जमीनों की अदला बदली का मुद्दा जबलपुर से भोपाल तक पहली बार किसी जनप्रतिनिधि द्वारा उठाया गया साथ ही साथ छावनी की मतदाता सूची से काटे गए 24000 लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई जो निरंतर जारी है।

नौकरी दो नहीं तो डिग्री वापस लो : नीरज कुंदन

सिहोरा में एसएसयूआई कार्यक्रम की दी गई जानकारी

सिहोरा , (एजेंसी)।

केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार हजारों बेरोजगारों को नौकरी देने में विफल साबित हो रही है। सत्ता हासिल करके सरकारें छात्रो युवाओं को भूल गई है और आज स्थिति यह है कि नौकरी देने के मुद्दे पर बात तक नहीं हो रही है। इसलिए देश के छात्र सारी डिग्री प्रधानमंत्री को वापस करके केन्द्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। उक्त आशय के विचार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने परिणिता पैलेस सिहोरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

कटनी में संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाते समय अल्प प्रवास पर सिहोरा में एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नौकरी दो नही तो डिग्री वापस लो का यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 फरवरी से प्रारंभ किया गया है जो देश के हर जिले में आयोजित होगा और छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हर स्तर पर सरकार से लड़ाई लड़ेगा छात्रों को बजट से काफी आशाएं थीं लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की जब नौकरी नही दे रही है तो बेरोजगार छात्र डिग्री वापस न करें तो क्या करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नगर आगमन पर समस्त कांग्रेस जनो ने पुष्प हार से स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक और एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विपिन बानखेड़े, प्रदेश प्रभारी नीतीश गौंड , ब्लॉक अध्यक्ष जितेन्द्र श्रीवास्तव ,अमोल चौरसिया, राजीव दीक्षित, संदीप ब्यौहार,सोनू त्रिपाठी कार्यक्रम संयोजक मीडिया प्रभारी, योगेश सिंह ठाकुर ब्लॉक अध्यक्ष एन एसयूआई,सजल कुरारिया नगर अध्यक्ष, आनंद पटेल, आलोक पांडेय, मोंटी गर्ग, मनीष खम्परिया, घनश्याम बडगैया, प्रदीप पटेल, आभास दुबे, शमशेर खान, ममता गोंटिया सहित सेवादल व एनएसयूआई के समस्त कार्यकर्ता एवं कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

डीएनए बारकोड से होगी पौधों की सटीक पहचान

जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी अनोखी और विश्व की एकलौती तकनीक का किया आविष्कार

जबलपुर , (एजेंसी)।

जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी अनोखी और विश्व की एकलौती तकनीक का आविष्कार किया है, जिसकी बदौलत पौधों की सटीक पहचान मुमकिन हो सकती है। उपरोक्त जानकारी देते हुए कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन ने बताया कि यूनिवर्सिटी के जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र के शोधकर्ता संचालक डॉ. शरद तिवारी, सहायक प्राध्यापक डॉ. कीर्ति तन्तवाय एवं सहशोधार्थी डॉ. नीरज त्रिपाठी ने पेटेन्ट ''डी.एन.ए. बारकोड फॉर स्पीशीज आइडेन्टीफिकेशन ऑफ सेज प्लान्ट्स एण्ड मेथड्स देयर ऑफ' विषयक तकनीक विकसित की है।

डी.एन.ए. बारकोड आधारित इस तकनीक से एक समान दिखने वाले पौधों (खासकर औषधीय महत्व के बिछौने जैसे घास कुल के पौधों) की पृथक पहचान आसानी से की जा सकती है। समूचे विश्व के कृषि वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, छात्रों एवं व्यवसायियों हेतु यह तकनीक बहुपयोगी साबित होगी। ज्ञात हो कि पेटेन्ट एक ऐसे शोध या नवाचार तकनीक पर भारत सरकार द्वारा अनुदत्त किया जाता है जो पहले से उपस्थित न हो साथ ही उसकी व्यवसायिक उपयोगिता हो। यूनिवर्सिटी ने पेटेन्ट हेतु 16 जनवरी 2017 को फाइल किया था, जिसे हाल ही में भारत सरकार के पेटेन्ट ऑफिस द्वारा अधिनियम 1970 के उपबंध के अनुसार 20 वर्ष की अवधि के लिये पेटेन्ट अनुदत्त किया गया है। इस बड़ी उपलब्धि से यूनिवर्सिटी में हर्ष का माहौल है। इस बड़ी उपलब्धि पर कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन, कुलसचिव रेवासिंह सिसोदिया, अधिष्ठाता कृषि संकाय डॉ. धीरेन्द्र खरे, संचालक अनुसंधान सेवायें डॉ. पी.के. मिश्रा, संचालक विस्तार सेवायें डॉ. (श्रीमति) ओम गुप्ता, संचालक शिक्षण डॉ. अभिषेक शुक्ला, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी संकाय डॉ. आर.के. नेमा, अधिष्ठाता कृषि कॉलेज डॉ. ए.के. भौमिक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. अमित शर्मा ने वैज्ञानिक दल को शुभकामनाएं दीं और सतत् अनुसंधानात्मक गतिविधियों में निरन्तरता बनाये रखने का आव्हान किया।

समकालीनता का निर्माण ही करती हैं विचारधाराएं : शुक्ल

जबलपुर ,**(एजेंसी)।** विचारधारायें ही समकालीनता का निर्माण करती हैं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र पुस्तक पाश्चात्य विचारधारा के गंभीर विवेचन को सरलता के साथ रखती है तथा उसे पठनीय बनाती है। उक्त जानकारी प्रो. अरूण शुक्ला ने बुधवार को शासकीय महाकोशल कॉलेज हिन्दी विभाग द्वारा प्रसिद्ध आलोचक डॉ. निशा तिवारी की पुस्तक पाश्चात्य साहित्य शास्त्र पर चर्चा के दौरान दी।आयोजन की अध्यक्षता डॉ. अरूण मिश्रा ने कहा कि डॉ. निशा तिवारी एक कुशल प्राचार्य व प्रशासक थीं, उससे बढ़कर एक गंभीर शिक्षक होने के साथ-साथ एक गंभीर आलोचक हैं। उन्होंने प्राचीन सेमेस्टर उत्तर आधुनिकता तक के विचार दर्शन की विवेचना की है। डॉ. संजुल शर्मा ने कहा कि यह पुस्तक विचारों की श्रृंखला को क्रमबद्ध रुप से सामने रखती है और आज के समकालीन साहित्य के आलोचना को प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर डॉ. किरण जैन, डॉ.वंदना शुक्ला, डॉ. मीना केलर, डॉ. तृप्ति उकास, डॉ. बलीराम अहिरवार, डॉ.रुचि अर्जुनवार आदि प्राध्यापक उपस्थित रहे।

कैम्पस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तीसरे दिन 41 आवेदकों को मिला रोजगार

जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कैम्पस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तीसरे दिन बुधवार को कुल 115 आवेदकों ने पंजीयन कराया। यहां मौजूद चार कंपनियों ने पंजीकृत युवाओं का साक्षात्कार लेकर 41 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया। उपसंचालक रोजगार एमएस मरकाम ने बताया कि गुरूवार 11 फ रवरी को भी कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जायेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन कटंगा स्थित जिला रोजगार कार्यालय उद्योग भवन कटंगा में किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से चयनित 42 आवेदकों में से 10 को भारतीय जीवन बीमा निगम जबलपुर 6 को यशस्वी टैलेंट मैनेजमेंट, 13 को संपूर्ण सॉल्यूशन्स के अलावा मेजर डिजायर में 12 आवेदकों को रोजगार मिला।

सीतारमण का विपक्ष को जवाबःवित्त मंत्री ने कहा सरकार विनिवेश कर रही है, घर के गहने नहीं बेच रही

मुंबई । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वह घर गहने बेच रही है। उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में देश के प्रमुख कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पहली बार विनिवेश को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाई है, ताकि जनता के टैक्स के पैसे का अच्छा इस्तेमाल हो। सरकार चाहती है कि कुछ खास सेक्टर में ही कुछ

गिनी-चुनी सरकारी कंपनियां हों और वे अच्छा परफॉर्म करें। सीतारमण ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम घर के गहने बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर की कीमती चीज को मजबूत किया जाता है। अभी इनकी सख्या काफी ज्यादा है और वे कमजोर हालत में हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी कंपनियों की संख्या घटनी चाहिए और उनका आकार बढ़ना चाहिए।

बजट में दो सरकारी बैंकों के रणनीतिक विनिवेश की हुई है घोषणा

1 फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले कारोबारी साल में IDBI बैंक के साथ दो सरकारी बैंकों का रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा। एक सरकारी साधारण बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाएगा। रणनीतिक विनिवेश का सीधा मतलब है निजीकरण।

बैंकिंग सेक्टर के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि विकास के लिए देश को भारतीय स्टेट बैंक के आकार के कम से कम 20 बैंकों की जरूरत है। बजट में उन्होंने कहा था कि रणनीतिक सेक्टर में सिर्फ सरकार ही नहीं रहेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। सरकार उन्हीं रणनीतिक सेक्टर्स में रहेगी, जहां बहुत जरूरी होगा।

कोविड सेस लगाने पर सरकार ने कभी विचार नहीं किया

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने कभी भी कोविड-19 टैक्स या सेस लगाने पर विचार नहीं किया। पता नहीं इसे लेकर मीडिया में चर्चा कैसे शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं इस महामारी से संघर्ष कर रही थीं, हमने इससे बचाव का रास्ता ढूंढ लिया था।

बेजोस ने कहा- 21 वीं सदी भारत कीःहर सेक्टर में उतर कर ऑन लाइन ई-कॉमर्स में बड़ी हिस्सेदारी लेना चाहती है अमेजन

नई दिल्ली। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस अब कंपनी के बोर्ड में भूमिका निभाएंगे। हाल में उन्होंने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की थी। लेकिन उनके नजरिए से 21 वीं सदी भारत की होगी। यही कारण है कि हाल के सालों में जेफ बेजोस ने भारत पर जमकर फोकस किया है। वे हर सेक्टर में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर रिलायंस जियो के ई-कॉमर्स और फ्लिपकार्ट पर होगा, जो इसी सेक्टर में मौजूद हैं।

बेजोस कुछ समय पहले भारत में थे

कुछ समय पहले जब बेजोस भारत में थे। वो मुकेश अंबानी और किशोर बियानी सहित उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं के साथ बंद दरवाजों में बैठकें कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड सितारों के साथ नजदीकियां बढ़ाई। प्रतिष्ठित ताजमहल का दौरा किया। बच्चों के साथ पतंग उड़ाया और भारतीय स्ट्रीट फूड का भी जायजा लिया। यहां तक कि उन्होंने मुंबई के एक किराना स्टोर से एक कस्टमर को पैकेज भी दिया और इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।

सीईओ पद से हटने के बाद काफी कुछ बदलेगा

उनके सीईओ के पद से हटने के बाद बहुत कुछ बदलेगा। वह अमेज़न बोर्ड को धीरे-धीरे सभी जिम्मेदारी दे देंगे। हालांकि वे बोर्ड में बने रहेंगे। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के प्रमुख एंडी जैसी को 2021 की तीसरी तिमाही में सीईओ की जिम्मेदारी दे दी जाएगी।बेजोस के नेतृत्व में अमेजन ने 2013 के रूप में भारत को एक रणनीतिक बाजार के रूप में पहचाना। अमेजन ने अब तक भारत के बाजार में 6.5 अरब डॉलर से अधिक की रकम लगा रखी है। यह ऐसे समय में देश में अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं जब यह फर्म ने चीन से अपने नाते तोड़ चुका है।

देश में कुछ खास है तो वह है लोकतंत्र- बेजोस

बेजोस ने पिछले साल अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि इस देश में कुछ खास है, वह है लोकतंत्र। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 21वीं सदी भारती की सदी बनने जा रही है। गतिशीलता, ऊर्जा हर जगह मैं जहां जाता हूं, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो आत्म-सुधार और विकास में काम कर रहे हैं।

ऑन लाइन मार्केट में अभी काफी अवसर

दरअसल, 1.2 ट्रिलियन डॉलर के रिटेल मार्केट में से सिर्फ 7त्न ही ऑनलाइन हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस के जियोमार्ट समेत उसके प्रतिद्वंदी आक्रामक तरीके से बाकी 93त्न बाजार पर नजर गड़ाए हुए हैं। देश में ऑनलाइन कॉमर्स का बाजार 2028 तक 200 अरब डॉलर तक जा सकता है।

बैंकों के निजीकरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए रिजर्व बैंक के साथ मिलकर करेंगे काम : सीतारमण

नई दिल्ली। सरकार बजट में घोषित बैंक निजीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बैंकों में अपनी हिस्सेदारी के मैनेजमेंट के लिए कोई बैंक निवेश कंपनी के गठन की योजना नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह जो बजट पेश हुआ उसमें सीतारमण ने विनिवेश योजना के तहत दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। इसे लेकर बैंक यूनियनों ने विरोध किया। प्रस्ताव के बारे में सीतारमण ने कहा कि हम

आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया पर काम चल रहा है। हालांकि, किस या किन बैंकों को बिक्री के लिये चुना जा रहा है सीतारमण ने ये बताने से इनकार कर दिया। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार इसके लिए तैयार होगी तो हम आपको बता देंगे।

बैड बैंक के बारे में बताते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) के लिए कुछ गारंटी देनी पड़ सकती है। हालांकि, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस समाधान को बैंकों ने ही पेश किया है और वही इसकी अगुवाई भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक धीरे-धीरे जोखिम से बाहर निकल रहे हैं।वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां पहले के खराब प्रबंधन की विरासत हैं। उन्होंने कहा, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। मुझे नहीं मालूम यह बात कहां से आ रही है। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूं। कम से कम यह मेरे सामने नहीं है। सीतारमण ने कहा कि अब नयी दिल्ली से मदद नहीं मांगी जा रही है न ही फोन बैंकिंग किया जा रहा है।

बैंक निवेश कंपनी पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री ने बैंकों को पेशेवर बनाने पर जोर दिया और कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।

एअर इंडिया को 13 साल का सबसे बड़ा घाटाःमहाराजा को बेचने में दिक्कत और बढ़ेगी, वैल्यूएशन घटने की आशंका

नई दिल्ली। सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया को बेचने में सरकार को और दिक्कत आ सकती है। आशंका है कि पिछले 13 सालों में इसको सबसे बड़ा घाटा होने जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसका घाटा 10 हजार करोड़ रुपए होने की आशंका है। ऐसे में इसका वैल्यूएशन घट सकता है।

2007 में एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइंस को मिलाया गया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब से इंडियन एअर लाइंस को एअर इंडिया में मिलाया गया है, तब से अब तक का यह सबसे बड़ा घाटा होगा। इंडियन एअर लाइंस को 2007 में मिलाया गया था। महाराजा के नाम से प्रसिद्ध एअर इंडिया को कोविड-19 से सबसे ज्यादा फटका लगेगा। इसके रेवेन्यू और घाटा में और ज्यादा अंतर आने की आशंका है।

8 हजार का कारोबारी नुकसान

बताया जा रहा है कि इसका कारोबारी नुकसान 8 हजार करोड़ रुपए हो सकता है। जबकि 2 हजार करोड़ रुपए का अन्य नुकसान होने की संभावना है। 2017-19 में इसका नुकसान 5,300 करोड़ रुपए था। इसके बाद इसका घाटा और बढ़ता गया।

2018-19 में घाटा बढ़कर 8,500 करोड़ रुपए तो हुआ, पर 2019-20 में यह मामूली घट कर 8 हजार करोड़ रुपए हो गया।

बजट में 4 हजार करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा

हालिया पेश बजट में एअर इंडिया के 4 हजार करोड़ रुपए जुटाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि चालू वित्त वर्ष में यह 6 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसमें से अब तक इसने 4 हजार करोड़ रुपए जुटा भी लिया है। पैसे की जरूरत इसलिए है ताकि इसका ऑपरेशन चालू रखा जाए। यानी इसे चलाया जाता रहे।

20 साल से बिक रही है एअर इंडिया

बता दें कि एअर इंडिया को बेचने की कोशिश काफी लंबे समय से हो रही है। 20 साल पहले से इसे बेचा जा रहा है। उस समय 20त्न हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही थी। हालांकि इस समय इसकी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। अब तक ढेर सारी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। पर सरकार की शर्तों और इसके भारी-भरकम कर्ज के कारण कोई खरीदार नहीं आ पा रहा है।

टाटा ग्रुप की दिलचस्पी

हालांकि टाटा ग्रुप अभी भी इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। क्योंकि टाटा ग्रुप ने ही इसकी शुरुआत की थी। टाटा ग्रुप के सामने यह दिक्कत है कि वह एअर एशिया और विस्तारा में पहले से ही भागीदार है। एअर एशिया में एअर एशिया अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। ऐसे में टाटा ग्रुप इसकी पूरी हिस्सेदारी खरीद सकता है।

2017 में 74 पर्सेंट हिस्सा बेचने की योजना थी

सरकार 2017 में एअर इंडिया में 74फीसदी हिस्सेदारी बेच रही थी। पर बाद में इसे बढ़ाकर 100फीसदी कर दिया गया था। इसके साथ ही एअर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। एअर इंडिया पर 38,366 करोड़ रुपए का कर्ज है। जबकि सरकारी विभागों पर एअर इंडिया का 500 करोड़ रुपए का बकाया है। एअर इंडिया के पास कुल 46 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें जमीन, बिल्डिंग, फ्लीट और अन्य संपत्तियां हैं।

धोखाधड़ी में जेलः क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड के जरिए निवेशकों के 700 करोड़ रु. से ज्यादा हड़पे, कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई

नई दिल्ली। अमेरिका में दो क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड के फाउंडर ने निवेशकों के 100 मिलियन डॉलर करीब 728 करोड़ रुपए हड़प लिए। अब कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।

ऑस्ट्रेलिया के 24 साल के युवक ने हड़पे रुपए

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, 24 साल के ऑस्ट्रेलियाई युवक स्टीफन हे किन ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्जिल सिग्मा और VQR मल्टीस्ट्रेटजी फंड नाम से दो क्रिप्टो हेज फंड की स्थापना की। स्टीफन पर सिक्युरिटीज फ्रॉड का आरोप था। मेनहट्टन की फेडरल कोर्ट ने स्टीफन को दोषी ठहराया है। DOJ के मुताबिक, इन दोनों फंड ने 2017 से 2020 के दौरान करीब 100 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाया।

मुनाफे वाली निवेश रणनीति के जरिए निवेशकों को लुभाया

होमलैंड सिक्युरिटी इन्वेस्टीगेशन के स्पेशल एजेंट ने जांच में पाया कि स्टीफन ने निवेशकों को मुनाफे वाली निवेश रणनीति के जरिए लुभाया। निवेशक स्टीफन के झांसे में आ गए और उन्हें 100 मिलियन डॉलर की चपत लग गई।

पर्सनल इन्वेस्टमेंट में खर्च की निवेशकों की राशि

अमेरिका के अटॉर्नी ऑड्रे स्ट्रॉस के मुताबिक, स्टीफन ने दोनों फंड से निवेशकों के करीब 90 मिलियन डॉलर निकाल लिए। स्टीफन ने इस राशि को पर्सनल इन्वेस्टमेंट में खर्च कर दिया। स्ट्रॉस के मुताबिक, स्टीफन के कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने ड्क्त्क्रमल्टीस्ट्रेटजी फंड से पैसे चुराने का प्रयास किया है। मौजूदा समय में इस फंड के पास निवेशकों की करीब 24 मिलियन डॉलर की राशि है।

हेज फंड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग पर लगेगी लगाम

अमेरिका का बाइडेन प्रशासन मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन सारे लूपहोल खत्म करने की तैयारी कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो इससे प्राइवेट-इक्विटी और हेज फंड के सामने संकट आ सकता है। बाइडेन प्रशासन बराक ओबामा के कार्यकाल में बनाए गए नियम को फिर से लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस नियम को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हटा दिया गया था।

जनवरी में 12,980 करोड़ निकाले-8 महीने से शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड, डेट में लगा रहे हैं पैसे

नई दिल्ली। शेयर बाजार की तेजी में म्यूचुअल फंड लगातार इक्विटी से पैसे निकाल रहे हैं। जनवरी में इन्होंने 12 हजार 980 करोड़ रुपए निकाले हैं। यह लगातार आठवां महीना है जब फंड हाउसों ने पैसे निकाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयरों की कीमतें मार्च के निचले स्तर से दोगुनी बढ़ गई हैं और मुनाफा कमाने के लिए अब इसे बेचा जा रहा है।

एफआईआई का निवेश जारी

हालांकि म्यूचुअल फंड की लगातार शेयरों की बिक्री के बाद भी शेयर बाजार की तेजी जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार पैसे लगा रहे हैं। जनवरी में इन्होंने करीबन 19 हजार 472 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। फरवरी में अब तक 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं। 2020 में इन्होंने कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है।

निवेशक बेच रहे हैं शेयर

जानकारों के मुताबिक, निवेशक इस समय शेयरों को बेच रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने दिसंबर में या जनवरी में शेयर बेचे हैं, उन्हें फायदा तो हुआ है, पर वही शेयर वो अगर अब बेचते तो कम से कम 30-40त्न का और फायदा उन्हें मिल जाता। प्रमुख शेयरों में जैसे SBI, TCS, HDFC बैंक, HDFC असेट मैनेजमेंट, इंफोसिस आदि शेयर जनवरी के

पहले हफ्ते की तुलना में इस समय अच्छे खासे बढ़े हैं।

ग्रोथ पर फोकस वाला बजट और अर्थव्यवस्था में सुधार

ग्रोथ पर फोकस वाला बजट का सबसे बड़ा इवेंट आ चुका है। अर्थव्यवस्था में सुधार और कोरोना की वैक्सीन शुरू हो चुकी है। ऐसे में इक्विटीज अभी भी उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मुनाफा वाला साधन है, जो इसमें निवेश जारी रखे हैं। शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 में म्यूचुअल फंड हाउसों ने कुल 56 हजार 400 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से निकाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में म्यूचुअल फंड हाउसों ने 12 हजार 980 करोड़ रुपए शेयर बाजार से निकाले हैं। इसके साथ ही जून से देखा जाए तो अब तक कुल 94 हजार 800 करोड़ रुपए के शेयर फंड हाउसों ने बेचे हैं।

नवंबर में 14 हजार 492 करोड़ निकाले

नवंबर मे म्यूचुअल फंड हाउसों ने 14 हजार 492 करोड़ रुपए निकाले थे जबकि अक्टूबर में 4,134 करोड़ रुपए निकाले थे। सितंबर में 9,213 करोड़ रुपए और अगस्त में 9,195 करोड़ रुपए निकाले गए थे। जुलाई में 612 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए थे। हालांकि पिछले साल जनवरी से मई तक कुल 40 हजार 200 करोड़ रुपए का निवेश फंड हाउसों ने बाजार में किया था। इसमें से अकेले 30 हजार 285 करोड़ रुपए मार्च में निवेश किया गया था।

मार्च से बाजार में भारी गिरावट आई थी

मार्च से बाजार में गिरावट शुरू हुई थी। मई के बाद बाजार में तेजी आनी शुरू हुई थी। विश्लेषकों के मुताबिक, इक्विटी का वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका है इसलिए निवेशक इस पैसे को निकाल कर डेट और अन्य साधनों में निवेश कर सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा अमीर निवेशक निकाल रहे हैं। जबकि रिटेल निवेशक अभी भी म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में निवेश को बनाए रखे हैं।

विदेशी निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं

विदेशी निवेशक लगातार बाजार में निवेश कर रहे हैं इसलिए म्यूचुअल फंड हाउस अपने पैसे को निकाल कर पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे हैं। यानी वे डेट में इसे लगाकर इक्विटी में अपना निवेश कम कर रहे हैं। यही कारण है म्यूचुअल फंड हाउसों ने जनवरी में डेट में 11 हजार 382 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में दिसंबर में कुल 26 हजार 73 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। जबकि इसी दौरान 36 हजार 220 करोड़ रुपए निकाले गए। यह दोनों आंकड़ा नवंबर की तुलना में बढ़ा है।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी, हाई कोर्ट की निगरानी में हो रही है हाथरस कांड की जांच

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआइ इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की जांच कर रही है। यह मामला पिछले साल सितंबर का है, जिसमें 19 वर्षीय एक युवती की कथित दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि चूंकि स्थानीय पुलिस को जांच से हटा दिया गया है और सीबीआइ मामले की जांच कर रही है, इसलिए इस स्तर पर आशंकाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश पर हाथरस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है।

रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर, 2020 को अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की थी कि याचियों ने अनुरोध किया है कि इस मामले की केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकारियों को निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया जाए और जरूरी हो तो केस सीबीआइ को सौंपा जाए या फिर एसआइटी गठित की जाए। इस जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाए।

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह उचित होगा कि जांच की निगरानी हाई कोर्ट अपने तरीके से करे और उसके निर्देशानुसार एजेंसी अपनी रिपोर्ट उसे पेश करे।

जर्मनी और आस्ट्रेलिया में भी बढ़ी भारतीय कामगारों की मांग, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए

नई दिल्ली । जापान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के बाद जर्मनी और आस्ट्रेलिया भी प्रशिक्षित भारतीय कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं। जर्मनी ने खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित भारतीयों को लेने की इच्छा जताई है, वहीं आस्ट्रेलिया ने कई क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित भारतीय युवाओं में रुचि दिखाई है। इसके अलावा कई देशों में प्रशिक्षित कामगारों की कमी और भविष्य में होने वाली मांग का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। ताकि उनकी जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। कौशल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जर्मनी और आस्ट्रेलिया के साथ प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति के लिए शुरुआती बातचीत हो चुकी है और दोनों देश इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के साथ जल्द ही समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक बार समझौता होने के बाद इन देशों के मानक और जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। जाहिर है कि इन प्रशिक्षित युवाओं को इन देशों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके पहले जापान और यूएई के साथ प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता हो चुका है।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत में उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ भारतीय युवाओं को विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और उसके लिए जरूरी प्रशिक्षण का पता लगाने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन और अर्नस्ट एंड यंग के साथ मिलकर एक स्टडी भी कराई गई है। इसमें विश्व में प्रशिक्षित कामगारों की मौजूदा कमी के साथ-साथ अगले पांच साल में होने वाली जरूरत का अंदाजा लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल की बीमारी मुआवजे के लिए निर्दिष्ट अपंगता की श्रेणी में नहीं

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल की बीमारी के लिए अपंगता मुआवजा मांगने वाले भारतीय जहाजरानी निगम के एक पूर्व नाविक की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व नाविक को नौकरी के दौरान यह बीमारी नहीं हुई। अदालत ने यह भी कहा कि दिल की बीमारी मुआवजे के लिए निर्दिष्ट अपंगता की श्रेणी में नहीं आती।

नवल किशोर शर्मा नामक नाविक ने राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड समझौता के उपखंड 21 के तहत अपंगता मुआवजा की मांग की थी, जिसे भारतीय जहाजरानी निगम (एससीआइ) ने ठुकरा दिया था। एससीआइ ने कहा था कि यह जहाज पर ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में चोट लगने का मामला नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने भी एससीआइ के आदेश को सही ठहराते हुए शर्मा की याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की तीन सदस्यीय पीठ ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का यह मानना सही है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की स्थिति पर याचिकाकर्ता को विकलांग व्यक्ति अधिनियम की धारा 47 के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

पीठ ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता की बीमारी और जहाज पर ड्यूटी के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। याचिकाकर्ता की डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की स्थिति न तो निर्दिष्ट अपंगता है और न ही विकलांगता के व्यापक परिपेक्ष्य के समान है, जिससे समाज में वह पूरी तरह से भागीदारी नहीं कर पाता हो।

Bigg Boss 14

जैस्मीन भसीन

ने रुबीना दिलैक के खिलाफ रचा षडयंत्र, जानें क्या है माजरा

'बिग बॉस 14' अब मजेदार मोड़ पर पहुंच गया है. घर में सभी कंटेस्टेंट्स के कनेक्शन एक-एक करके एंट्री ले चुके हैं, जिसका प्रसारण आज के एपिसोड में होना है. शो का हिस्सा रह चुकीं जैस्मीन भसीन ने भी अली गोनी का कनेक्शन बनकर घर में धमाकेदार एंट्री मारी है. जैस्मीन भसीन ने घर में आते ही राहुल वैद्य का शुक्रिया अदा किया है और इसके बाद वो अली गोनी से अपने इश्क का इजहार करती हुई दिखाई दीं. 'बिग बॉस 14' के लेटेस्ट एपिसोड में भी जब-जब रुबीना दिलैक अपनी बात सामने रख रही थी, तब-तब जैस्मीन भसीन का रिएक्शन देखने लायक था.

जैस्मीन भसीन का हर रिएक्शन साफ जाहिर कर रहा था कि वो एक पल के लिए भी रुबीना दिलैक को अपनी नजरों के सामने नहीं देख सकती हैं. घर में एंट्री मारने के कुछ ही देर बाद जैस्मीन भसीन ने रुबीना दिलैक के खिलाफ षड़यंत्र रचना शुरू कर दिया. आप 'बिग बॉस 14' के प्रोमो में जैस्मीन को साफ तौर पर अली गोनी को रुबीना दिलैक से दूर रहने की हिदायत दे रही हैं. प्रोमो में अली गोनी का रिएक्शन ही बता रहा है कि वो जैस्मीन भसीन की बातों से सहमत नहीं हैं. ऐसे में हो सकता है कि फिनाले तक दोनों आपस में ही उलझे रहें. जैस्मीन के शो से जाने के बाद से अली और रुबीना दिलैक के रिश्तों में सुधार नजर आया था.

बता दें कि बिग बॉस 14 से बेघर होने के बाद जैस्मीन भसीन ने रुबीना दिलैक को चालाक और ढोंगी बताया था. शो से बाहर होने के बाद भी जैस्मीन भसीन ने रुबीना के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया. ऐसे में शो में दोबारा एंट्री लेने के बाद जैस्मीन रुबीना दिलैक के खिलाफ क्या-क्या रुख अपनाती हैं.

नेहा कक्कड़

के पिता चाय-समोसे बेच कर करते थे परिवार का गुजारा, जानें सिंगर के स्ट्रगल की कहानी

सिंगर नेहा कक्कड़ को आज हर कोई जानता है. उनके गानों को लोग खूब पसंद करते हैं. अब तक के अपने करियर में नेहा कक्कड़ ने ढेर सारे सुपरहिट गानें गाए हैं. वह सिर्फ अपने गानों की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी सेल्फी की वजह से भी चर्चित रही हैं. लेकिन आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां तक का सफर काफी संघर्ष भरा था. नेहा कक्कड़ को ये सफलता आसानी से नहीं मिली है. नेहा कक्कड़ भी कई मौकों पर अपनी जिंदगी के सफर को बयां कर चुकी हैं. आइये जानते हैं नेहा कक्कड़ के संघर्ष की कहानी...

आज नेहा कक्कड़ का नाम टॉप सिंगर्स में शुमार है. नेहा गाने के अलावा सिंगिंग रियलिटी शो भी जज करती हैं. उन्होंने एक बार सिंगिंग शो सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स में अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहन सोनू को दिया था. शो में नेहा ने कहा था, मैंने चार साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था. सोनू दीदी ने भी कम उम्र से ही गाना शुरू किया था. मेरा परिवार म्यूजिक से ताल्लुक नहीं रखता था. सोनू दीदी ही हमारे घर की पहली सिंगर थीं. अगर वो नहीं होती तो शायद आज मैं सिंगर नहीं होती. मैं आज जो कुछ भी हूं, सोनू दीदी की वजह से ही हूं. सोनू और टोनी (भाई) मेरी जान हैं.नेहा छोटे शहर से आई हैं. इसलिए उन पर कई तरह की पाबंदियां थीं. उन्होंने एक बार बताया था कि छोटे शहर के लोगों को बड़े सपने देखने का भी अधिकार नहीं होता है. ऐसे में बस कोशिश रहती थी कि हम सभी कुछ अच्छा कर सकें. हमारे घर की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं होती थी. पापा सोनू दीदी के कॉलेज के बाहर चाय-समोसा बेचा करते थे, जिस वजह से बच्चे उनपर तंज कसते थे. बता दें कि नेहा कक्कड़ ने अपनी जिंदगी की दास्तां को गानों के माध्यम से भी सभी के सामने रखा है.नेहा ने आगे कहा था, टोनी भी तब बहुत छोटा था, लेकिन वह हम दोनों के लिए गाने बनाता था. आखिरकार, उसका गाना मिले हो तुम हमको हिट हुआ और इसे 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले.

ऐसे ही धीरे-धीरे हमें सफलता मिलती गई.यकीनन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और नेहा कक्कड़ ने इसे साबित भी किया है. नेहा ने न सिर्फ बड़े सपने देखे, बल्कि उनको पूरा भी किया. नेहा के पास आज खुद का आलीशान घर है और कई महंगी गाड़ियां भी हैं. नेहा अक्सर अपने पति के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

प्रभास की सालार के एक खास गाने में नजर आएंगी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा?

सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म सालार को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं. जनवरी में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी. फिल्म के मुहूर्त के दौरान यश सेट पर आए थे और प्रभास के साथ यश की तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इस फिल्म की शूटिंग अब हैदराबाद में तेजी से चल रही है. इस बीच ये खबर आ रही है कि बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा प्रभास की फिल्म सालार में एक स्पेशल सॉन्ग करते नजर आएंगी.

रिपोर्ट्स की माने तो सालार फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक स्पेशल सॉन्ग के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है. अगर प्रियंका ग्रीन सिग्नल देती हैं तो फिर प्रभास और प्रियंका के फैंस के लिए ये बेहद खुशी की बात होगी. प्रियंका अब एक इंटरनेशनल स्टार हो चुकी हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भारत ही नहीं विदेशों में भी है. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की नई किताब अनफिनिश्ड रिलीज हुई है. इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के दो हॉलीवुड प्रोजेक्ट मेट्रिक्स और टेक्स फॉर यू भी जल्द रिलीज होने वाले हैं.

फिलहाल सालार की शूटिंग रामागुड़म में चल रही है. इस फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास एक मेकैनिक का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट श्रुति हासन नजर आएंगी. ये पहली बार है जब श्रुति और प्रभास एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. प्रभास की इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं जबकि विजय किरागंडूर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. भुवन गौड़ा इस फिल्म के सिनेमैटोग्राफर हैं और रवि बसरूर फिल्म के म्यूजिक कंपोजर हैं.

मलाइका अरोड़ा ने शेयर की नई तस्वीर, फैंस ने निकाला अर्जुन कपूर के साथ कनेक्शन

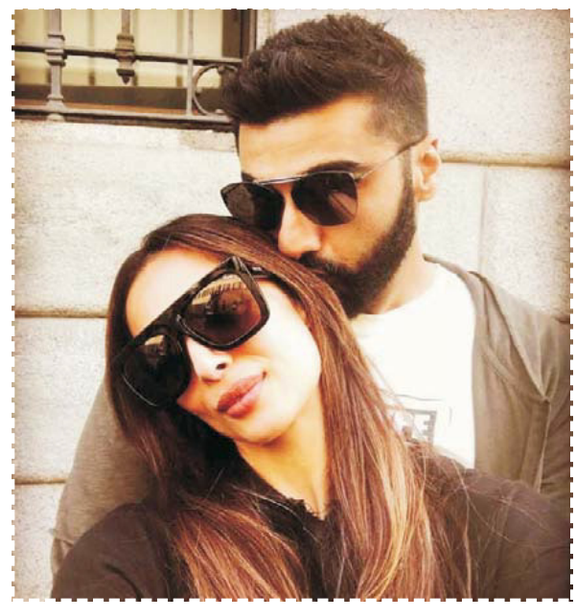

बॉलीवुड के लव बर्ड्स मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर ने जब से दुनिया के सामने अपना रिश्ता ऑफिशियल किया है, तब से वह सबके सामने अपना प्यार दिखाने में हिचकिचाते नहीं हैं. दोनों ने अपनी केमेस्ट्री से लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर दोनों अक्सर एक-दूसरे की तस्वीरों और वीडियों पर कमेंट्स करते रहते हैं. हाल ही में मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर उनके फैंस को लग रहा है कि मलाइका की इस तस्वीर का अर्जुन के साथ कोई कनेक्शन है.

दरअसल, मलाइका इस तस्वीर में शर्माते हुए नज़र आ ही हैं. उन्होंने इस तस्वीर का कैप्शन भी दिया- आपकी वजह से मैं ब्लश करती हूं बेबी. यह कैप्शन देख सबको लग रहा है कि मलाइका ने यह पोस्ट अर्जुन के लिए ही किया है. हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में अर्जुन का नाम नहीं लिया है.

अर्जुन और मलाइका का रोमांस लोगों को बहुत पसंद आता है. दोनों की उम्र में भले ही काफी अंतर हो, लेकिन उससे उनके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता है. उन्होंने 2019 में अर्जुन के जन्मदिन पर अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था. उस दिन मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अर्जुन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें बर्थडे विश किया था.

ऐसा पहली बार था, जब मलाइका ने अर्जुन के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी. हाल ही में दोनों नया साल मनाने के लिए साथ गोवा गए थे. दोनों अक्सर हॉलिडे पर भी साथ जाते हैं. इतना ही नहीं, लॉकडाउन में भी उन्होंने काफी समय एक साथ बिताया था.

पिछले 15 साल में इंग्लैंड सबसे सफल

इंग्लिश टीम ने भारत में 15 में से 4 टेस्ट जीते, बाकी 8 विदेशी टीमें मिलकर 54 में से 3 टेस्ट ही जीत सकीं

चेन्नई। भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड की टीम 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इंग्लैंड पिछले 15 साल में भारत का दौरा करने वाली सबसे सफल विदेशी टीम भी बन गई। उसने 2006 से लेकर अब तक भारत में 15 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 4 में उन्हें जीत मिली है। इस दौरान इंग्लिश टीम को 7 टेस्ट में हार मिली और 4 टेस्ट ड्रॉ रहे।

वहीं, टेस्ट खेलने वाली बाकी अन्य टीमों ने इस दौरान कुल 54 टेस्ट खेले, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 टेस्ट में ही जीत मिली। साउथ अफ्रीका ने 12 टेस्ट खेले। इसमें से 2 में उन्हें जीत मिली, 8 हारे और 2 टेस्ट ड्रॉ रहे। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 14 टेस्ट खेले। इसमें से वह सिर्फ 1 टेस्ट जीत सका, 10 हारे और 3 टेस्ट ड्रॉ रहे। इनके अलावा कोई भी टीम भारत में जीत दर्ज करने में विफल रही।

इंग्लैंड एशिया में सबसे सफल नॉन-एशियाई टीम बनी

इंग्लैंड टीम की एशिया में 30वीं टेस्ट जीत है। बतौर नॉन-एशियाई टीम इंग्लैंड सबसे सफल टीम है। ऑस्ट्रेलिया 28 जीत के साथ दूसरे और वेस्टइंडीज 26 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है।

एशिया में लगातार 6 टेस्ट जीतने वाली इंग्लैंड दूसरी विदेशी टीम

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही ऐसी नॉन एशियाई टीमें हैं, जिसने महाद्वीप में लगातार 6 या इससे ज्यादा टेस्ट में जीत हासिल की है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2002 से 2004 के बीच एशिया में लगातार 7 टेस्ट में जीत हासिल की थी। वहीं, इंग्लैंड ने 2018 से लेकर अब तक एशिया में लगातार 6 टेस्ट जीते हैं। इनके अलावा कोई भी टीम एशिया में लगातार तीन टेस्ट भी नहीं जीत सकी हैं।

घर में सबसे ज्यादा हार के मामले में चेपक दूसरे पर

भारत ने अपने घर में सबसे ज्यादा टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन में हारे हैं। भारत ने यहां 42 टेस्ट खेले। जिसमें से 13 में जीत और 9 में हार मिली। वहीं, चेन्नई का चेपक स्टेडियम इस मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत ने चेपक में 33 टेस्ट खेले। इसमें से 14 में जीत और 7 में हार मिली।

फीफा क्लब वर्ल्ड कप:बायर्न म्यूनिख फाइनल में पहुंचा, लेवानदॉस्की ने क्लब के लिए 275वां गोल दागा

दोहा। जर्मनी का फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। EFA चैंपियंस लीग विजेता बायर्न म्यूनिख ने सेमीफाइनल में मिस्र के क्लब अल अहली को 2-0 से हराया। रॉबर्ट लेवानडोस्की ने 17वें और 86वें मिनट में गोल किए। उनके बायर्न की ओर से 275 गोल पूरे हो गए हैं।

मूलर के नाम है क्लब से सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड

लेवानदॉस्की इस क्लब से 275+ गोल करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। गर्ड मुलर के नाम क्लब से सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने करियर में 518 गोल किए थे। बायर्न म्यूनिख का फाइनल में मैक्सिको के टाइग्रेस क्लब से 11 फरवरी को सामना होगा।

बायर्न जीत सकता है साल का छठा मेजर टाइटल

अगर बायर्न जीतता है तो सालभर में उसका यह छठा मेजर टाइटल होगा। बायर्न ने 2020 में घरेलू लीग बुंदेसलिगा, जर्मन कप, चैंपियंस लीग, जर्मन सुपर कप, यूरोपियन सुपर कप जीते थे। पहले क्लब वर्ल्ड कप पिछले साल दिसंबर में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित करना पड़ा।

सैयद किरमानी ने ऋषभ पंत को बताया प्रतिभा का खजाना

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को सीरीज जिताने में नायक रहे ऋषभ पंत के बल्लेबाजी की अक्सर तारीफ होती है। इस बीच भारत के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर सैयद किरमानी ने ऋषभ पंत को बल्लेबाज के तौर पर 'प्रतिभा का खजाना' करार दिया है। साथ ही उन्होंने विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत की तुलना 'पालने' के बच्चे से की है।

ऋषभ पंत को बताया प्रतिभा का खजाना

71 साल के पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ऋषभ पंत प्रतिभा का एक खजाना हैं, वह नैसर्गिक तौर पर शॉट खेलने वाले बल्लेबाज हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि विकेटकीपर के तौर पर उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। सैयद किरमानी ने कहा कि पंत को यह भी सीखना होगा कि कब बड़ा शॉट लगाना है, जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था।

कीपिंग के कुछ नुस्खे भी दिए

इतना ही नहीं उन्होंने पंत को विकेट कीपिंग के कुछ नुस्खे भी दिए। किरमानी ने कहा कि पंत को विकेट कीपिंग में बुनियादी सही तकनीक की जरूरत है, जो उनके पास नहीं एक कीपर की क्षमता का अंदाजा तभी लगाया जाता है जब वह स्टंप्स के निकट खड़ा होता है। किरमानी ने यह कहा कि पंत दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा विकेटकीपिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, जहां आप स्विंग और गेंद का उछाल देखकर उस मुताबिक अनुमान लगा सकते है। किरमानी ने कहा कि बल्लेबाज के तौर पर पंत को परिस्थितियों के हिसाब से खेलना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिस्बेन में पंत ने काफी संतुलित पारी खेली, जिससे हम पहली बार वहां जीत दर्ज कर सके। ऐसे कई मौके थे जब पंत भारत को जीत दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट गवां दिया। हालांकि, किरमानी ने ऑस्ट्रेलिया में उनकी बल्लेबाजी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में उसका खेल पसंद आया। जहां रक्षात्मक खेल की जरूरत थी वहां उसने रक्षात्मक खेला और जहां आक्रामक खेल की जरूरत थी वहां वह खुल कर खेला।

सुआरेज ने रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा

बार्सिलोना से एटलेटिको मैड्रिड में स्विच करते ही सबसे तेज 16 गोल दागे

रोनाल्डो की टीम कोपा इटैलिया के फाइनल में

रोम। उरुग्वे और एटलेटिको मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने युवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे इस सेंचुरी में किसी क्लब के लिए स्पेनिश लीग ला लीगा में सबसे तेज 16 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम था। उन्होंने 2009/10 में रियाल मैड्रिड के लिए पहले 17 मैच में 15 गोल दागे थे। रोनाल्डो का मौजूदा क्लब युवेंटस कोपा इटालिया के फाइनल में भी पहुंच गया है।

सुआरेज ने एटलेटिको मैड्रिड के लिए 17 मैच में 16 गोल दागे: सुआरेज ने 2020/21 सीजन में बार्सिलोना छोड़कर एटलेटिको मैड्रिड जॉइन किया था। एटलेटिको मैड्रिड जॉइन करने के बाद से वे बेहतरीन फॉर्म में हैं। उन्होंने नई क्लब के लिए पहले 17 मैच में 16 गोल दागे हैं। मंगलवार को सेल्टा विगो के खिलाफ ला लीगा के एक मैच में सुआरेज ने 2 गोल दागे। हालांकि, उनकी टीम को सेल्टा के खिलाफ 2-2 का ड्रॉ खेलना पड़ा। सेल्टा की ओर से सैंटी मिना और फाकुंदो फेरेरा ने गोल दागे।

रोनाल्डो ने 2009 में रियाल मैड्रिड के लिए 15 गोल दागे थे

सुआरेज से पहले यह रिकॉर्ड रोनाल्डो के नाम था। रोनाल्डो 2009 में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर स्पेनिश क्लब रियाल मैड्रिड जॉइन किया था, तब उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। सुआरेज ने 2014 में बार्सिलोना जॉइन किया था। वहां उन्होंने 283 मैच में 195 गोल दागे थे और क्लब के तीसरे हाइएस्ट गोल स्कोरर रहे।

2020 में सुआरेज ने बार्सिलोना छोड़ दिया था

2020 में रोनाल्ड कोमैन के बार्सिलोना कोच बनने के बाद उन्हें टीम से निकाल दिया गया। उन्होंने फिर एटलेटिको मैड्रिड जॉइन किया। सुआरेज अब तक करियर में 6 क्लबों के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने कुल 636 क्लब मैच खेले हैं और 419 गोल दागे हैं। उरुग्वे के लिए उन्होंने 116 मैच में 63 गोल दागे हैं।

रोनाल्डो की टीम युवेंटस कोपा इटालिया के फाइनल में

वहीं, रोनाल्डो की मौजूदा टीम युवेंटस ने मंगलवार को इंटर मिलान के खिलाफ सेमीफाइनल के दूसरे लेग में 0-0 से ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ टीम कोपा इटालिया के फाइनल में पहुंच गई। युवेंटस के होम ग्राउंड एलियांज स्टेडियम पर हुए इस मैच में रोनाल्डो ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। पहले लेग में युवेंटस ने इंटर मिलान को 2-1 से हराया था। इसलिए एग्रीगेट के आधार पर युवेंटस ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उनका सामना नैपोली और अटलांटा के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता टीम से होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज खेलने से मना किया

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के नहीं आने को खेल भावना के खिलाफ माना; ICC से हस्तक्षेप की मांग

सिडनी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पत्र लिखकर ऑस्ट्रेलिया के दौरा रद्द किए जाने पर हस्तक्षेप करने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के रिस्क की वजह से मार्च में होने

वाले दौरे को रद्द कर दिया था। इस कारण CSA को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। CSA की ओर से लिखे गए पत्र में ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से हटने के निर्णय को खेल भावना के खिलाफ बताया गया है।

WTC का हिस्सा थी साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज

ऐसा इसलिए क्योंकि यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। CSA अंतरिम बोर्ड के चेयरमैन स्टावरोस निकोलाऊ ने कहा कि हम जैसे फाइनेंशियल तौर पर कमजोर बोर्ड पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हालांकि ICC को किसी तरह के निर्देश देने से पहले यह स्थापित करना होगा कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ तनाव है।

अगर ऐसा कुछ होता है तो रिजॉल्यूशन कमेटी बनानी होगी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत नहीं की गई है। पत्र इसलिए भेजा गया है कि महामारी के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे मैनेज किया जाए। क्रिकेट साउथ अफ्रीका इस कारण भी नाखुश है, क्योंकि सख्त बायो सिक्योर बबल बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आई। उन्हें VVIP का दर्जा दिया गया था।

रत की ओर से बीते एक साल में टेस्ट में सिर्फ 1 शतक, इस दौरान इंग्लैंड के लिए 10 और पाकिस्तान के लिए 7 शतक लगे

चेन्नई। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 227 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट ने पहली पारी में शानदार दोहरा शतक जमाया। वहीं, भारत की ओर से एक भी शतक नहीं लगा। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के लिए शतकों का सूखा पिछले करीब एक साल से चल रहा है। 2020 से अब तक भारत ने सात टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें भारत की ओर से सिर्फ एक शतक बना है। इस दौरान दुनिया की तमाम अन्य टेस्ट टीमों की ओर से भारत की तुलना में ज्यादा शतक जमाए गए हैं। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज भी भारत से आगे हैं।

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बल्लेबाज सबसे आगे

1 जनवरी 2020 से अब तक टेस्ट क्रिकेट में 44 शतक जमाए गए हैं। इंग्लैंड की ओर से 12 टेस्ट में 10 शतक बने हैं। वहीं, पाकिस्तान की ओर से 8 टेस्ट में 7 शतक जमाए गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली खुद शतकों के सूखे से जूझ रहे हैं। वे अब लगातार चार टेस्ट मैच बिना शतक जमाए खेल चुके हैं। इनमें दो टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक-एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ रहे हैं। विराट ने आखिरी शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ जमाया था। वहीं, ओपनर रोहित शर्मा लगातार पांच टेस्ट से शतक नहीं जमा पाए हैं। रोहित ने आखिरी टेस्ट शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में अक्टूबर 2019 में जमाया था।

रूट इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तान बने: 55फीसदी टेस्ट में इंग्लिश टीम को जीत दिलाई; वॉन, स्ट्रॉस और कुक से आगे निकले

चेन्नई। जो रूट इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गए हैं। उन्होंने अब तक 47 टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी की है, जिसमें से टीम को 26 टेस्ट में जीत मिली। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड के टेस्ट जीतने का दर 55.31फीसदी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड माइकल वॉन के नाम था। वॉन की कप्तानी में इंग्लैंड ने 51 में से 26 टेस्ट में जीत हासिल की थी। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड के जीतने का दर करीब 51फीसदी था।

रूट के सेंचुरी लगाने पर कभी नहीं हारी इंग्लिश टीम

रूट ने अब तक टेस्ट में 20 सेंचुरी लगाई है। इसमें से 5 डबल सेंचुरी हैं। जिन 20 टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी लगाई, उनमें से एक भी मैच इंग्लैंड नहीं हारा है। टीम को 16 टेस्ट में जीत मिली। जबकि, 4 टेस्ट ड्रॉ रहे।

भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे रूट: इंग्लिश कप्तान जो रूट को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने पहली पारी में 218 रन की पारी खेली। यह उनके करियर का 5वां दोहरा शतक रहा। रूट ने सिक्स लगाकर अपनी डबल सेंचुरी पूरी की। वे सिक्स लगाकर 200 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर बने। रूट 100वें

टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। रूट का यह (218 रन) भारत के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर भी है। इससे पहले भारत के खिलाफ उनका बेस्ट स्कोर 154 रन नॉटआउट था।वे भारतीय जमीन पर पिछले 10 साल में दोहरा शतक जमाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन गए। इससे पहले नवंबर, 2010 में न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम ने हैदराबाद टेस्ट में 225 रनों की पारी खेली थी।

रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने एशिया में 6 टेस्ट जीते

रूट ने अब तक एशिया में 6 टेस्ट में कप्तानी की है। इसमें से सभी टेस्ट में इंग्लैंड की जीत मिला। इस दौरान इंग्लिश टीम ने श्रीलंका को उनके घर में 5 टेस्ट और भारत को भारत में 1 टेस्ट में हराया।

सिर्फ साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड ने एशिया में बतौर कप्तान उनसे ज्यादा टेस्ट जीते हैं।

टेस्ट के लिए बेस्ट है चेन्नई जैसी पिच:22 साल BCCI के चीफ क्यूरेटर रहे दलजीत ने कहा- टेस्ट को जिंदा रखना है तो ऐसी ही पिच बनाओ

चेन्नई। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रन से हरा दिया। टेस्ट के पांचों दिन इंग्लैंड टीम हावी रही। इस वजह से मैच के पहले दिन से चेपक की पिच चर्चा में रही। शुरुआत में इसे बेजान बताया गया, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा तो पिच की असल रंगत भी सामने आई।

इस पिच को लेकर दिग्गज पिच क्यूरेटर दलजीत सिंह ने भास्कर से बात की। दलजीत 22 साल (1997 से 2019) BCCI के चीफ क्यूरेटर रहे हैं। वे 1974-75 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने वाली बिहार टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। मेरे मुताबिक चेन्नई की पिच टेस्ट क्रिकेट के लिए परफेक्ट रही। मैं इस पिच को 100फीसदी अंक देता हूं। पिच क्यूरेटर वी रमेश कुमार ने टेस्ट को ध्यान में रखकर बेहतरीन पिच तैयार की। वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

इस पिच पर सबके लिए कुछ न कुछ था। यहां दोहरा शतक बना, एक स्पिनर ने पारी में 6 विकेट लिए। तेज गेंदबाजों को भी कामयाबी मिली। स्लिप में कैच भी पकड़े गए। हम कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ था। पहले दिन पिच बल्लेबाजों के लिए

बेहतर रही। यहां काफी रन बने। वहीं दूसरे दिन से गेंदबाजों को मदद मिलनी शुरू हो गई। पांचवे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए चेन्नई जैसी पिच ही तैयार की जानी चाहिए। इस पिच पर कभी बल्लेबाज हावी रहे, तो कभी गेंदबाज। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों विकेट लेने में सफल हुए। दोनों टीमें दो-दो बार ऑलआउट हुई। अंतिम दिन टेस्ट का रिजल्ट भी निकला। टेस्ट में रिजल्ट आने पर ही इसके प्रति लोगों की रुचि बनी रहेगी।

टेस्ट में ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए, जिस पर दो या तीन दिन में रिजल्ट आ जाए। ऐसी पिच भी नहीं तैयार की जानी चाहिए, जहां बिना परिणाम के ही टेस्ट समाप्त हो जाए। अगर टेस्ट को जिंदा रखना है तो विभिन्न देशों के बोर्ड को चेन्नई जैसे पिच को बढ़ावा देना होगा। टेस्ट के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पिच तैयार करना होगा, ताकि पांचवें दिन तक इसका रिजल्ट आए और लोगों की रुचि पहले दिन से अंतिम दिन तक बनी रहे।

इस पिच पर टॉस जीतना महत्वपूर्ण था। अगर भारतीय टीम के पक्ष में टॉस जाता तो शायद परिणाम अलग भी हो सकता था। हम सभी भारतीय चाहते हैं कि इंडिया जीते। इंग्लैंड ने टॉस जीता और उसके बल्लेबाजों ने पिच का फायदा उठाया किसी भी मेजबान देश की कोशिश रहती है कि वह अपने लिहाज से पिच तैयार करे। घरेलू कोच और कप्तान की सलाह पर पिच को अंतिम रूप दिया जाता है। हर देश घरेलू सीरीज में इसका फायदा उठाता है। भारत भी उठाता है, तो इसमें गलत नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पहले टेस्ट में जैसी पिच थी, वह आदर्श थी।

ऑस्ट्रेलियन ओपन: वर्ल्ड नंबर-1 बार्टी ने कोविनिच को सिर्फ 44 मिनट में हराया; दो बार की चैंपियन अजारेंका पहले राउंड से बाहर

मेलर्बन। दुनिया की नंबर-1 महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी बेहद आसानी से ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गईं। ऑस्ट्रेलिया की बार्टी ने मोंटेनेग्रो की डेंका कोविनिच को 6-0, 6-0 से हराया। टॉप सीड बार्टी ने पहले राउंड का मुकाबला सिर्फ 44 मिनट में जीत लिया। वहीं, पूर्व नंबर-1 विक्टोरिया अजारेंका उलटफेर की शिकार हो गईं।

मुख्य दौर में पहुंचने वाली मिस्र की पहली खिलाड़ी

दो बार की पूर्व चैंपियन बेलारूस की अजारेंका को अमेरिका की गैरवरीय जेसिका पेगुला ने 7-5, 6-4 से हराकर पहली बार दूसरे राउंड में जगह बना ली। इस बीच, 24 साल की मेयर शेरिफ किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर का मैच जीतने वाली मिस्र की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। शेरिफ ने फ्रांस की कोल पैक्वेट को 7-5, 7-5 से हराया। अन्य मैचों में प्लिसकोवा, एनेट कोंटावेट, कोको गॉफ, हीथर

वाटसन, सोफिया केनिन ने जीत दर्ज की।

नडाल 15वीं बार दूसरे राउंड में पहुंचे

दूसरी वरीयता प्राप्त राफेल नडाल 15वीं बार दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। स्पेन के नडाल ने सर्बिया के लास्लो डेरे को 6-3, 6-4, 6-1 से हराया। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने कनाडा के वासेक पोसपिसिल को 6-2, 6-2, 6-4 से मात दी। भारत के सुमित नागल पहले राउंड में हारकर बाहर हो गए। नागल को लिथुआनिया के रिकार्डेस बेरानकिस ने 6-2, 7-5, 6-3 से हराया।

स्टीफानोस सितसिपास, बोरना कोरिच, फेलिसियानो लोपेज, एलेक्स डि मिनॉर भी दूसरे राउंड में पहुंच गए।